₹ 20

ट्राइब वॉइस

RNI No. / Title Code: CHHHIN17199 | हिंदी मासिक पत्रिका | वर्षः 01, अंकः 01, अगस्त-सितंबर | 2020 पेज-40

छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना

छत्तीसगढ़: गौ सेवकों को मिलेगा "गोबर-धन"

अगस्त क्रांतिः अंगेजी हुकूमत की जड़े हिला दी

भारत : वैश्विक अगुआ !

चीन के जाल में उलझता नेपाल

RNI No. / Title Code: CHHHIN17199 | हिंदी मासिक पत्रिका | वर्ष: 01, अंक: 01, अगस्त -सितंबर | 2020 पेज-40

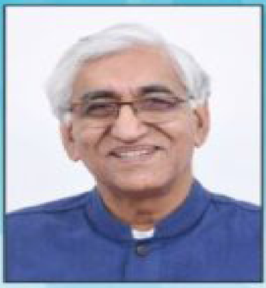

श्री टी.एस. सिंहदेव
मान. स्वास्थ्य मंत्री
छत्तीसगढ़

जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा

27 जून से 24 जुलाई 2020

आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी
सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी

आओ ये ज़िम्मेदारी निभाते हैं

जहाँ सपने सिर्फ़ सजते नहीं, सच हो जाते हैं, एक ऐसा प्लान बनाते हैं

परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं

आओ ज़िम्मेदारी निभाते हैं, प्लान बनाते हैं

सही उम्र में शादी करते हैं, और सोचकर बच्चे

एक खुशहाल परिवार बनाते हैं, ज़िम्मेदारी निभाओ, प्लान बनाओ

अस्थायी गर्भ निरोधक छाया एवं अन्तरा को अपनाएं

अधिक जानकारी के लिए
निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र से सम्पर्क करें

छत्तीसगढ़ संवाद

सभी शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क परिवार कल्याण के साधन जैसे, निरोध, मौखिक गोली, इंजेक्शन कापर टी की सुविधा उपलब्ध है । COVID19 महामारी के दौरान स्थाई साधन पुरूष एवं महिला नसबंदी में प्रतिबंध होने की स्तिथि में अपना पंजीयन निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में कराएं (स्तिथि सामान्य होने पर सेवाएं पुनः प्रारम्भ की जाएगी)। अपने निकट के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य केंद्र अथवा टोल फ्री नं. 104 से संपर्क करें ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़

RNI No. / Title Code: CHHHIN17199

ट्राइब वॉइस

वर्ष : 01, अंक : 01, अगस्त 2020

संपादक
मनोज कुमार साहू
सह-संपादक
नरसिंह देवांगन
कार्यकारी संपादक
संदीप कुमार सिंह
प्रबंध संपादक
भारती वर्मा
सलाहकार संपादक
डॉ. आनंद पहारिया
डॉ. नरेन्द्र त्रिपाठी
ग्राफिक डिजाइनर
अनीश चौधरी
विज्ञापन / प्रसार
योगेश साहू
सौरभ गुप्ता

ब्यूरो संवाददाता
रायपुर : दामिनी बंजारे
दुर्ग : कोमल राम साहू
कांकेर : वैभव चौहान
सरगुजा : क्षितिज चंदेल
संवाददाता
मुकेश वर्मा
पल्लवी साहू

संपादकीय कार्यालय
102, सीजी हाईट्स, प्रेम कुंज, सिविल लाइन, रायपुर, छत्तीसगढ़ -492001

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक
संपादक मनोज कुमार साहू के लिए 102, सीजी हाईट्स, प्रेम कुंज, सिविल लाइन, रायपुर, छत्तीसगढ़ -492001 व प्रिंटेक स्केनर मिश्रा बाड़ा तात्यापारा चौक, रायपुर (छ.ग.) के पास से मुद्रित एवं 102, सीजी हाईट्स, प्रेम कुंज, सिविल लाइन, रायपुर, (छ.ग.) -492001 से प्रकाशित।

"ट्राइब वॉइस" में प्रकाशित लेख, रचनाएं व विचार लेखक की व्यक्तिगत विषयवस्तु और विश्लेषण पर आधारित होते है। प्रकाशित लेखों में निहित विचारो व तथ्यों से संपादक या "ट्राइब वॉइस" की सहमति होना अनिवार्य नहीं है। किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र रायपुर (छत्तीसगढ़) होगा।

RNI No./Title Code: CHHHIN17199 | हिंदी मासिक पत्रिका | वर्ष: 01, अंक: 01, अगस्त -सितंबर | 2020 पेज-40

इस अंक में

स्पेशल स्टोरी

26

10 चीन के जाल में उलझता नेपाल

भगवा न राम नेपाली थे और उनकी जन्मस्थली अयोध्या भारत में नहीं, नेपाल के बीरगंज जिले में स्थित थी- कहकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दक्षिण एशिया के सांस्कृतिक इतिहास को धता बताने की कोशिश

14 भारत : वैश्विक अगुआ !

कोरोना महामारी के पश्चात भारत के सामने अवसर के दरवाजे खुल रहे हैं। इस अवसर को भुनाकर भारत स्वयं को दुनिया के लिए एक रोल मॉडल और प्रेरणा के रूप में स्थापित कर सकता है।

06 >>>>>>>>> पेसा कानून
08 >>>>>>>>> गोधन न्याय योजना
20 >>>>>>>>> मध्यप्रदेश : अमानवीय सोच से कब मिलेगी राहत ?
22 >>>>>>>>> छत्तीसगढ़: गौ सेवकों को मिलेगा "गोबर-धन"
28 >>>>>>>>> उत्तर प्रदेश : क्या समाज को एनकाउंटर पसंद है?
30 >>>>>>>>> अंग्रेजी सीखने के आसान टिप्स
32 >>>>>>>>> जहाँ जैसा मिजाज व माहौल वहाँ वैसा पहनावा
36 >>>>>>>>> क्लाइमेट चेंज व ग्लोबल वार्मिंग
38 >>>>>>>>> क्या खूब जिया है जी भर...!

हम क्यों ...

›› “ट्राइब वॉइस” आदिवासी समाज की मानवीय व सामाजिक पहलू पर मुखर आवाज उठाने वाली एक मासिक पत्रिका है।

›› “ट्राइब वॉइस” का उद्देश्य आदिवासी समाज से जुड़े मूलभूत मुद्दों पर सामाजिक व राजनैतिक विमर्श हेतु सकारात्मक वातावरण बनाना है।

“ट्राइब वॉइस” का प्रयास आदिवासी समाज को मुख्यधारा सें जोड़ने हेतु एक सेतू की भूमिका का निर्वाह करना है।

›› “ट्राइब वॉइस” का प्रयास संकुचित मानसिकता और आपसी टकराव से उपर उठकर उच्चस्तरीय विचार-विमर्श हेतु वैज्ञानिक व तार्किक वातावरण का माहौल बनाना है।

›› आदिवासी जनमानस, विशेषकर उनके जीवन संघर्ष के नीतिपरक और मूल्यनिष्ठ मुद्दों तथा इनसे जुड़ाव रखने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक मुद्दों पर प्रकाश डालना “ट्राइब वॉइस” की विषयवस्तु है।

›› “ट्राइब वॉइस” की संपादकीय नीति प्रगतिशील, आधुनिक, उदारवादी व सर्वधर्म सम्भाव की भावनाओं पर आधारित है।

›› “ट्राइब वॉइस” भारत के बहुलतावादी समाज की विविधताओं से सृजित समस्त सोच, विचार, दृष्टिकोण और मान्यताओं को अपने में समाहित करने का सार्थक प्रयास करेगा।

›› आदिवासी जगत से सरोकार रखने वाले बुद्धिजीवियों व समाजशास्त्रियों हेतु एक विचार मंच बनाने का प्रयास है “ट्राइब वॉइस”।

›› यदि आप “ट्राइब वॉइस” से जुड़ना चाहते हैं या फिर अपना कोई विचार व शोध कार्य प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप “ट्राइब वॉइस” में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो उसका भी तहेदिल से स्वागत है। ...

धन्यवाद...।

भारती वर्मा

कोरोना के बाद क्या बदलाव हो सकते हैं?

मनोज कुमार साहू

कोरोना महामारी के पश्चात भारत के सामने कई चुनौतियाँ मुँहबाएं खड़ी हैं। मौजूदा समय में सबसे अहम चुनौती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की है जिसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयासरत कर रही है। लेकिन इन प्रयासों में एग्रीकल्चर सेक्टर नदारत ही नजर आता है जिस पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और जिसकी लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि सेक्टर पर ही निर्भर है। निरंतर हो रहे जलवायु परिवर्तन व मौसम के बदलते मिजाज के चलते गड़बड़ा रही खेती जिस पर सरकारी कृषि नीतियां और दूसरे कई कारण यह बताते हैं कि देश के कई शहर जल्द ही अरबन फार्मिंग अपनाने की ओर अग्रसर होंगे।

यह तय मानिये कि जनसंख्या ही बढ़ेगी, जमीन नहीं, फिर खेती वाली जमीन तो हर हाल में ही घटेगी कुछ आभासी विकास के नाम पर हथिया ली जायेगी कुछ वास्तविक विकास की बलिवेदी चढ़ेगी जो बचेगी उसे शहरीकरण लील जायेगा। फिर किसान बनने या बने रहने में भी रुचि किसे है। किसानी घाटे का धंधा है गांव वाले इसे छोड़ वैकल्पिक व्यवस्था देख रहे हैं। एक देशी सर्वेक्षण यह बताता है कि 60 फीसदी किसान अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहते और तकरीबन इतने ही खेती किसानी और गांव छोड़ शहर में काम काज कर रहे अपने बच्चों के पास रहना चाहते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले दिनों में भारत, ब्राजील, पश्चिमी अफ्रीका और मैक्सिको में लोगों के सामने भुखमरी झेलनी पड़ सकती है।

सदियों से गांव ही शहरों के लिए खाद्यान्न और फल सब्जियां उपजाते और उन्हें शहर तक पहुंचाते थे पर भविष्य में शहरों को अपना खाना खुद उपजाना होगा। मुंबई के उपनगरीय इलाकों में कई लोग छोटे-छोटे भूखड़ों पर खेती कर बिना फर्टिलाइजर और कीटनाशक का प्रयोग किए ऑरगेनिक फल- सब्जियां उगा रहे हैं। ये अपनी उपज को मुंबई तथा नकदीकी बाजार में बेच रहे हैं। दिल्ली में यमुना के किनारे और आसापास बड़े पैमाने पर सब्जियां उगायी जा रही हैं। धीरे-धीरे इसका चलन अन्य शहरों में भी बढ़ रहा है जो कि एक अच्छे संकेत है।

यदि हम एनर्जी सेक्टर की बात करें तो क्लीन एनर्जी अभियान के तहत बिजली बनाने के लिये हवा, धूप और नाभिकीय ऊर्जा पर निर्भरता बढाने का अभियान समूचे संसार में है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर सोलर एनर्जी पर बहुत है और वे नाभिकीय ऊर्जा को भी बढावा देना चाहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन में दिक्कत यह है कि बहुत कठिनाई से हासिल दुर्लभनाभिकीय तत्व यूरेनियम की बिजली उत्पादन की क्षमता का महज एक फीसदी का ही इस्तेमाल हो पाता है और वह इसके बाद परमाणु कचरा बन जाती है। इस तरह यह यह बेहद महंगी पड़ती है।

पर वैज्ञानिक इस बात को लेकर उम्मीदों से भरे हैं कि नया नाभिकीय तत्व थोरियम इसके काम आयेगा तो स्थितियां बिल्कुल बदल जायेंगी। थोरियम धरती पर ज्यादा मात्रा में मौजूद है यूरेनियम के मुकाबले इससे न सिर्फ ज्यादा बिजली बनाया जा सकता है, बल्कि कम ऊर्जा लगेगी और कचरा भी कम निकलेगा। इस तरह यह यूरेनियम से सस्ता और बेहतर विकल्प होगा। इसी तरह सौर ऊर्जा में भी क्रांतिकारी बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। अततः यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में एनर्जी सेक्टर व एग्रीकल्चर सेक्टर में भारी बदलाव देखने के मिल सकते हैं। #

सीजी में 'पेसा' कानून को जमीन पर उतारने की कवायद शुरू

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री सिंहदेव ने आदिवासी समाज और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से की चर्चा

रायपुर

छत्तीसगढ़ में 'पेसा' (Panchayatiraj Extension in Scheduled Area) कानून को लागू करने गंभीर पहल शुरू हो गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने आज अपने निवास कार्यालय में सर्व आदिवासी समाज तथा पंचायतीराज सशक्तिकरण व वनाधिकार के लिए काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से 'पेसा' को जमीन पर उतारने नियम तैयार करने के संबंध में विचार-विमर्श किया। उन्होंने चर्चा में शामिल सभी लोगों से प्रदेश में इस कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने सुझाव मांगे। आदिवासी समाज और नागरिक संगठनों के अनेक प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी चर्चा में शामिल हुए।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार 'पेसा' को लागू करने प्रतिबद्ध है। जनजातीय समाज के हितों की रक्षा और वनांचलों के विकास में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने में 'पेसा' महती भूमिका निभाएगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार 'पेसा' को लागू करने प्रतिबद्ध है। जनजातीय समाज के हितों की रक्षा और वनांचलों के विकास में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने में 'पेसा' महती भूमिका निभाएगा।

इससे न केवल उनकी संस्कृति, परंपरा, रीति-रिवाजों और पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित रखा जा सकेगा, बल्कि उनके कल्याण के लिए जल, जंगल और जमीन के साथ अन्य प्राकृतिक संसाधनों को भी सहेजा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि 'पेसा' अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए संवेदनशील विषय रहा है। इसे लागू करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के रहवासियों, समुदायों, जनप्रतिनिधियों और आदिवासी मुद्दों के जानकारों के सुझावों को शामिल कर नियम तैयार किए जाएंगे।

श्री सिंहदेव ने कहा कि 'पेसा' के लिए नियम बनाने आज शुरू हुई चर्चा का विस्तार किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों वाले जिलों और विकासखंडों के लोगों से भी चर्चा कर उनके सुझावों को इसमें शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 'पेसा' के सभी 38 प्रावधान प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके, इसके लिए सभी स्तरों पर वृहद चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। पंचायत विभाग इस कानून को अमल में लाने वाले दूसरों राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के नियमों का भी अध्ययन कर रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायतीराज और 'पेसा' कानून की आत्मा को बरकरार रखते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की प्रभावी रीति-नीति तय की जाएगी।

आदिवासी समाज और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने 'पेसा' पर चर्चा के दौरान ग्रामसभा के सशक्तिकरण, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, रीति-रिवाजों, परंपरा और संस्कृति के संरक्षण, जमीन अधिग्रहण, ग्राम कोष, वनवासियों के कल्याण तथा नई विकास परियोजनाएं शुरू करने के संबंध में अनेक सुझाव दिए।

आदिवासी समाज और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने 'पेसा' पर चर्चा के दौरान ग्रामसभा के सशक्तिकरण, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, रीति-रिवाजों, परंपरा और संस्कृति के संरक्षण, जमीन अधिग्रहण, ग्राम कोष, वनवासियों के कल्याण तथा नई विकास परियोजनाएं शुरू करने के संबंध में अनेक सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि 'पेसा' के लिए नियम बनाते समय वर्तमान राजस्व और वन कानूनों का भी अध्ययन जरूरी है। इसे प्रभावी ढंग से लागू करने यदि इनमें संशोधन की जरूरत हो तो उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के लिए समग्र नियम आवश्यक हैं।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री अरविंद नेताम और पूर्व सांसद श्री सोहन पोटाई ने 'पेसा' पर अमल के लिए आदिवासी समाज को चर्चा में शामिल करने और उनसे सुझाव लेने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री सिंहदेव को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की महत्वपूर्ण चर्चा के लिए पहली बार आदिवासी समाज को आमंत्रित किया गया है। इससे सरकार की गंभीरता और प्रतिबद्धता पता चलती है। श्री नेताम ने कहा कि राज्य के लिए यह मील का पत्थर स्थापित करने का सुअवसर है कि वह 'पेसा' के लिए एक बेहतर और प्रभावी नियम बनाकर देश में मॉडल बने। 'पेसा' के हर क्लॉज के लिए पूरी गंभीरता से नियम बनाने की जरूरत है।

सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ की विशेषताओं के आधार पर 'पेसा' के लिए नियम बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने इसकी प्रारूप समिति में आदिवासी संस्कृति और जन-जीवन के जानकार व्यक्तियों को शामिल करने का भी सुझाव दिया।

बैठक में सर्व आदिवासी समाज के सर्वश्री बी.एस. रावटे, एन.एस. मंडावी, अकबर राम कोर्राम, मोहन कोमरे, प्रकाश ठाकुर, विनोद नागवंशी, नकुल चंद्रवंशी, अश्वनी कांगे और तुलसी मंडावी उपस्थित थे। गैर-सरकारी संगठनों से सर्वश्री गौतम बंदोपाध्याय, आलोक शुक्ला, सुदेश टीकम, अनुभव शोरी, संदीप सलाम, विजेन्द्र, सुश्री सरस्वती ध्रुव और सुश्री सुलक्षणा नंद चर्चा में शामिल हुईं। सामाजिक कार्यकर्ता सर्वश्री रमेश अग्रवाल, विजय भाई और सुश्री शालिनी गेरा तथा आदिवासी समाज के सर्वश्री अनूप टोप्पो, बसंत कुजूर और सुभाष ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपने सुझाव दिए। #

ग्रामीणों के लिए रोजगार और आय का साधन बनी "गोधन न्याय योजना"

छत्तीसगढ़ राज्य के मैदानी जिले हों या सुदूर वनांचल के जिले, सभी जगह गोधन न्याय योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीणों की माली हालत में सुधार का सबब बनते जा रही है।

रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन की सुराजी गांव योजना के तहत नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी के विकास और गोधन न्याय योजना से ग्रामीण क्षेत्रों स्वावलंबन एवं विकास की बयार बहने लगी है। शासन की उक्त दोनों योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली है। गोधन न्याय योजना से पहले गोबर सिर्फ गोबर था, जिसका कोई मूल्य न था। व्यर्थ हो जाता था। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी सुराजी योजना के तहत गांवों में निर्मित गौठानों में पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ ही ग्रामीणों को आय मूलक गतिविधियों से जोड़ने की अवधारणा से जैविक खाद के उत्पादन की शुरूआत हुई। गोधन न्याय योजना ने राज्य में जैविक खाद के उत्पादन की प्रक्रिया में कई गुना तेज रफ्तार दे दी है। इसके तहत गोबर की खरीदी के कारण अब राज्य के लगभग 4400 गौठानों में जैविक खाद का उत्पादन महिला समूहों द्वारा किया जाने लगा है। गोबर से जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया ने पूरे राज्य में पशुधन और गोबर प्रबंधन को एक दिशा दे दी है। यह तब्दीली संतुलित विकास की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है, जिससे ग्रामीण, किसान, मजदूर समृद्ध और खुशहाल हो रहे हैं। जैविक खाद से पोषक तत्वों से भरपूर खाद्यान्न उत्पादन होगा।

गोधन न्याय योजना ग्रामीणों के रोजगार और आय का एक बढ़िया माध्यम बनते जा रही है। ग्रामीण अंचल में इस योजना को लेकर लोगों में अच्छा खासा उत्साह है। इस योजना के जरिए राज्य में पशुधन की देखभाल को लेकर जहां एक ओर लोगों में

वर्मी कम्पोस्ट खाद की हाथों-हाथ बिक्री और इससे महिला समूह को होने वाले मुनाफे ने शासन की सुराजी गांव योजना के तहत निर्मित गौठानों और गोधन न्याय योजना की सार्थकता को स्वमेव प्रमाणित किया है।

जागरूकता आई है, वहीं दूसरी ओर अब पशुधन से मिलने वाला गोबर लोगों की आमदनी का जरिया भी बन गया है। गोधन न्याय योजना शुरू होने से गौठानों की रौनक बढ़ गयी है। महिला समूह सुबह से शाम तक गोबर खरीदी और इसके माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट खाद के निर्माण में जुटी रहती हैं। वर्मी कम्पोस्ट खाद की हाथों-हाथ बिक्री और इससे महिला समूह को होने वाले मुनाफे ने शासन की सुराजी गांव योजना के तहत निर्मित गौठानों और गोधन न्याय योजना की सार्थकता को स्वमेव प्रमाणित किया है।

छत्तीसगढ़ राज्य के मैदानी जिले हों या सुदूर वनांचल के जिले, सभी जगह गोधन न्याय योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीणों की माली हालत में सुधार का सबब बनते जा रही है। राज्य के सीमावर्ती सूरजपुर जिले में छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना के माध्यम से गौठानों में पर्याप्त मात्रा में गोबर की आवक को देखते हुए वहां की स्वयं सहायता समूहों द्वारा वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आदर्श गौठान ग्राम पंचायत केशवनगर में शिव महिला ग्राम संगठन की महिलाओं ने कृषि विभाग से विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त कर वर्मी कम्पोस्ट बनाने का काम शुरू किया है। केशवनगर गौठान में 86.13 क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है। इससे वर्मी खाद तैयार की जा रही है। जिले के गौठानों में महिला समूहों द्वारा उत्पादित वर्मी खाद को सुराजी सूरजपुर ब्रांड नाम से किसानों एवं उद्यानिकी विभाग की नर्सरी एवं वन विभाग को सप्लाई की जा रही है। इस योजना के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को गांव में ही रोजगार मिला है और उनकी आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होने लगी है। #

गोधन न्याय योजना के माध्यम से गौठानों में पर्याप्त मात्रा में गोबर की आवक को देखते हुए वहां की स्वयं सहायता समूहों द्वारा वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने की तैयारी शुरू कर दी है।

चीन के जाल में उलझता नेपाल

भगवान राम नेपाली थे और उनकी जन्मस्थली अयोध्या भारत में नहीं, नेपाल के बीरगंज जिले में स्थित थी-कहकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दक्षिण एशिया के सांस्कृतिक इतिहास को धता बताने की कोशिश ही नहीं की है।

ट्राइब वॉइस नेटवर्क

ऐसे समय में जब भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव बना हुआ है, नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने अयोध्या पर एक विवादास्पद टिप्पणी की है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। ओली ने कवि भानुभक्त की जयंती के अवसर पर अपने आधिकारिक आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, "भारत अपने यहां फर्जी अयोध्या बनाकर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ कर रहा है। वास्तविक आयोध्या नेपाल के बीरगंज के एक गांव में है।" ओली ने कहा कि भगवान राम नेपाली थे। नेपाल के कई नेताओं ने खुलकर ओली के इस बयान का विरोध किया है। नेताओं ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच वैसे भी तनाव की स्थिति बनी हुई है ऐसे में ओली को ऐसे दावों से बचना चाहिए।

नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा, "हमने जनकपुर में जन्मीं सीता का विवाह किसी भारतीय राजा के साथ नहीं किया बल्कि सीता का विवाह भारत के नहीं अयोध्या के राम से हुआ था जो कि नेपाल में है।" ओली ने कहा कि इतनी दूर से कोई राजा कैसे सीता से विवाह करने के लिए जनकपुर आ सकता है क्योंकि उस समय संचार और परिवहन के साधन नहीं थे। उन्होंने कहा, "उनकी अयोध्या को लेकर काफी विवाद है जबकि हमारी अयोध्या थोरी गांव में है जिसको लेकर कोई विवाद नहीं है।"

ओली ने दावा करते हुए कहा कि विज्ञान और ज्ञान का विकास नेपाल में हुआ था। नेपाल के प्रधानमंत्री के ऐसे बयान से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के सह-अध्यक्ष कमल थापा ने ओली की आलोचना करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री की ओर से ऐसे आधारहीन और अप्रमाणिक वक्तव्य का आना सही नहीं है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ओली भारत-नेपाल के संबंधों में मौजूदा कड़वाहट को कम करने की बजाए उसे और बढ़ाना चाहते हैं"

भगवान राम नेपाली थे और उनकी जन्मस्थली अयोध्या भारत में नहीं, नेपाल के बीरगंज जिले में स्थित थी-कहकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दक्षिण एशिया के सांस्कृतिक इतिहास को धता बताने की कोशिश ही नहीं की है बल्कि वर्तमान व भावी पीढ़ियों को गुमराह करने का गहरा षड्यंत्र किया है। यह ओली के पिछले कुछ दिनों से चीनी शह पर चल रहे भारत विरोध की सबसे खराब कड़ी है।

अबतक वे तीन भारतीय इलाकों को नेपाली नक्शे में दिखाकर शत्रुता की भौगोलिक रेखाएं खींचने, हिंदी के प्रचलन पर रोक लगाकर भाषायी अलगाववाद खड़ा करने की कोशिश और भारत के निजी चैनलों पर पाबंदी लगाकर मनोरंजन व समाचार के भारतीय स्रोत को सुखाने का प्रयास कर चुके हैं।

लेकिन 13 जुलाई को उन्होंने नेपाल के आदिकवि भानुभक्त आचार्य की जयंती पर रामायण की ऐतिहासिक व परंपरा को नकारने का बड़ा और गहरा चालाकी भरा कदम उठाया। यह नई पीढ़ी के सामने नया तथ्य रखकर भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक सूत्रों से अलगाव पैदा करने की चाल है।

कार्ल मार्क्स की धर्म को अफीम मानने की धारणा को मानते हुए कम्युनिस्टों का धर्म के प्रति शत्रुता की हद तक व्यवहार होता है। धर्म के प्रति तटस्थ होना गलत नहीं लेकिन धार्मिक आस्थाओं को अतार्किकता से खंडित करना, खराब कम्युनिस्ट होने की निशानी है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ओली ऐसे ही खराब कम्युनिस्ट हैं। भारत विरोध में वे अपनी ही पार्टी के अन्य नेताओं के विपरीत सांस्कृतिक परंपराओं को नष्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं जो दोनों देशों के लोगों के सह अस्तित्व को ही आगे चलकर कठिन बना सकता है। वे इस चेष्टा में अपने देश की लोकस्मृति, लोकचेतना और लोकश्रुति को भी नकारना चाहते हैं।

ओली ने जिन भानुभक्त की जयंती पर रामकथा की नई और मनमानी स्थापना दी, उन्होंने उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में तुलसीदास की तरह रामकथा "सातकांड रामायण" की रचना कर इसे घर-घर पहुँचाया था। रोचक बात यह है कि भानुभक्त खुद वाराणसी में पढ़े और यहीं उनकी कृति पहली बार प्रकाशित हुई। उनकी रामकथा बाल्मीकि रामायण व अध्यात्म रामायण से प्रेरित है। इस कथा में भी राम को अयोध्या का राजकुमार बताया गया है। वह अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। ओली ने इसे नकारते हुए कहा कि भारत ने नेपाल पर सांस्कृतिक आक्रमण किया और इतिहास से छेड़छाड़ की गई।

जनकपुर, जो नेपाल में स्थित है, वहां की राजकुमारी का विवाह किसी भारतीय राजकुमार (राम) से नहीं हुआ था। राम नेपाली थे जो बीरगंज जिले के कस्बे ठोरी के पास अयोध्या में जन्मे थे। यह अटपटी और अद्भुत मान्यता रखी जा रही है। नेपाली

लेखक और पूर्व विदेश मंत्री रमेशनाथ पांडेय ने पूछा कि आप अयोध्या को कहीं भी बता देंगे लेकिन वहाँ सरयू कहाँ से लाएँगे। सच यह है कि ठोरी में राम जन्मभूमि की स्थापना से खुद नेपाली ही इत्तेफाक नहीं रखते जबकि वे भी अयोध्या को तीर्थ मानते रहे हैं।

ओली का यह सवाल भी बेहूदा ही कहा जाएगा कि राम विवाह करने के लिए इतनी दूर जनकपुर कैसे आते? अयोध्या से नेपाल की सीमा महज़ 167 किमी है और जनकपुर की दूरी 500 किमी से कुछ ही ज्यादा है। जब राम रामेश्वरम तक ढाई हजार किमी की पदयात्रा कर सकते हैं तो जनकपुर दूर कैसे है? बाल्मीकि रामायण में दूरी का उल्लेख इस तरह है-"राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण तीन रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरी पहुँचे।"

ओली इतिहास को विकृत करने के लिए प्राचीन समय के आवागमन व पैदल चलने के इतिहास से भी अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। ऐसा करके असल में वे राम के महानायकत्व को भी खत्म करना चाहते हैं जिसको पूरा दक्षिण एशिया प्राचीनकाल से आदर देता आ रहा है। रामायण व महाभारत की कथाओं से जनमानस ने अपने को इस तरह जोड़ लिया है कि देश-विदेश में कई स्थानों को उनसे सीधा जुड़ा हुआ बताया गया है। जिस तरह नेपाल के बाल्मीकि आश्रम के बारे में कहा जाता है कि लव-कुश का पालन यहीं हुआ, उसी तरह के बाल्मीकि आश्रम भारत के कई हिस्सों में इसी मान्यता के साथ स्थापित हैं। आस्था इन मान्यताओं को कहीं भी क्षति नहीं पहुंचाती। इंडोनेशिया, मॉरीशस आदि देशों में अयोध्या और रामकथा से जुड़े प्रतीक स्थापित कर लिए हैं लेकिन वे भी राम की उत्पत्ति के बारे में ऐसे बेहूदा दावे नहीं करते। वहाँ के विद्वान भी रामकथा को एक पैनएशिया फिनामिना मानते हैं। ये देश कभी भारतीय सांस्कृतिक आक्रमण की बात नहीं कहते। तो क्या वामपंथी सरकारें ही सांस्कृतिक परंपराओं को विकृत करने और खत्म करने का एजेंडा लेकर आती हैं? नेपाल इसे साबित करता है।

ओली की चालाकी यह है कि वे केवल इतिहास में झूठ को ठूँसकर अपने ही लोगों को बहकाना नहीं चाहते बल्कि यह कहकर कि भारत ने नकली अयोध्या बना ली है, भारत विरोध को धार्मिक व सांस्कृतिक आक्रामक दृष्टि भी देना चाहते हैं। आश्चर्य है कि कभी दुनिया का एकमात्र हिंदू देश रहा नेपाल एक गुट की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते जन-मन की आस्था के नायक राम के बारे में विवाद खड़ा कर रहा है। यह भी याद रखना चाहिए कि नेपाल को चीन से आर्थिक लाभ मिल सकता है, भारत की तरह सांस्कृतिक-धार्मिक-सामाजिक रिश्ता नहीं।

वर्तमान नेपाल 1768 में अस्तित्व में आया। आदिकाल में अयोध्या और अन्य

भारतीय राजवंशों का भौगोलिक भूभाग रहा है। यहां भी तब वर्तमान बिहार और अन्य पड़ोसी राज्यों की तरह अनेक छोटे-छोटे राजकुल विद्यमान थे। जिनमें से कुछ बिहार से संबद्ध रहे। वहाँ के राजवंश अयोध्या के सूर्यवंशी राजाओं के निकट संबंधी रहे हैं। साथ ही वह भारत के सांस्कृतिक और हिंदू इतिहास का अभिन्न हिस्सा रहा है इसलिए इसमें अलग कथानक कहने की गुंजाइश वैसे भी नहीं रही। ओली ऐसा कर इतिहास को नकारना चाहते हैं जिसे नेपाल की जनता ही नहीं स्वीकार कर रही है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के ही उपप्रमुख विष्णु रिजल ने मीडिया से कहा कि कोई व्यक्ति अप्रमाणित, पुराणविरुद्ध और विवादास्पद बातें कहकर विद्वान नहीं बन जाता। लेकिन मामला विद्वान बनने का ही नहीं है। यह भारत विरोध को नया आधार देने का है। जैसा कि नेपाल की ही राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सह अध्यक्ष कमल थापा ने कहा कि ओली भारत से रिश्ते बिगाड़ना चाहते हैं।

श्रीराम और अयोध्या सम्बन्धी विवादास्पद बयान से नेपाली प्रधानमंत्री श्री ओली खुद ही अपने बुने जाल में उलझ गए। इससे भारत सहित नेपाल में भी हंगामा हुआ। नेपाली लोगो ने भी व्यापक विरोध जाहिर किया। विश्वव्यापी प्रतिक्रियाएं हुयी तो नेपाली विदेश मंत्रालय ने चीनी शैली में अपनी सफाई पेश की कि नेपाली प्रधानमंत्री का किसी की भावनाओ को ठेस पहुँचाने का कोई मकसद नहीं था। नहीं था? फिर ऐसा बोला क्यों? उसका कोई जवाब नहीं। उन्हें व्यापक विरोध के कारण नेपाल ने क्षमा-अहसास का कूटनीतिक नाटक किया। वैसे इसके पीछे चीन के फैलाया हुआ जाल हैं, जिसमे नेपाल में बुरी तरह से उलझा हुआ है।

अब जो भी हो प्रधानमंत्री ओली साहेब की कुर्सी पर खतरे के बादल मडरा रहे हैं। वे अपनी कुर्सी बचाने के लिए चीन की उँगलियों पर चलने को मजबूर बताये जा रहे हैं। नेपाल भारत का पुरातन मित्र है। भाई-भाई है। एक जान दो शरीर जैसी स्थिति रही है। आने वाले दिनों में भी वही पुरानी स्थिति आने वाली है। क्योंकि चीन, नेपाल व वहां के निवासियों की नज़र में बुरी तरह से एक्सपोज़ होने लगा है।विश्व जानता है चीन की विश्वसनीयता शून्य के बराबर है।पूरे विश्व को कोरोना रोग देने वाला चीन के बुरे दिन शुरू हो गए है, रही बात श्रीराम की। ये तो श्री ओली साहेब को भी पता है। पता था कि श्रीराम अयोध्या के थे, हैं और सदैव रहेंगे। श्रीराम जन्म भूमि को लेकर भारत के दुश्मनों ने कई प्रकार षड्यंत्र किये। छल प्रपंच किये। श्रीराम जन्म भूमि को लेकर भारत में 492 वर्षो तक मुकदमा चला। अंततः श्रीराम की महिमा भौतिक व नैतिक रूप से पुनःस्थापित हुयी। अब उस अयोध्या में जल्द ही भव्य व विशाल श्रीराम मंदिर बनेगा। श्रीराम भारत के अयोध्या के ही थे।उनकी प्राणप्रिय सीता जी जनकपुर की थी।श्रीराम के साथ विवाह के बाद अयोध्या आई।मेरे को लगता है कि प्रधानमन्त्री श्री ओली सीता जी की चर्चा करना चाहते होंगे श्रीराम का नाम बोल गए।परन्तु ये भी श्रीराम का चमत्कार ही कहा जायेगा जब एक घोर वामपंथी व्यक्ति किसी देवता का नाम और जन्म स्थान के बारे सार्वजनिक मंच से चर्चा कर रहा हो। उसमे भी श्री राम की महिमा निहित है।

सच कहते हैं श्रीराम की महिमा अपरम्पार है। कहते है एक नास्तिक को राम नाम का जाप के लिए कहा गया था, परन्तु वो आदतन नहीं बोला, पर उपहास के तौर पर "मरा-मरा" बोलने लगा, जो बाद में स्वाभाविक तौर पर सुर बदल गया। वो "राम-राम" हो गया। अंततः उसे पूर्ण मुक्ति मिली। उसकी आत्मा तृप्त हुयी। इसे कहते हैं श्रीराम की महिमा। श्रीलंका के लिए बनाये गए श्रीराम सेतु को लेकर भारत व विदेशो में हिन्दू धर्म व भारत के दुश्मनों द्वारा उसके अस्तित्व को नकारने कि पूरी कोशिशें की गयी थी। कई षड्यंत्र रचे गए थे। सब फेल हो गए। भारत में कांग्रेस पार्टी सरकार ने कई नाटक किये। श्रीराम सेतु को नकारने को लेकर कई ऐसे उपक्रम किये जो बाद असफल रहे। अमेरिका के वैज्ञानिक संस्थान नासा ने जब श्रीराम सेतु का नक्शा व अवशेष का चित्र जारी किया तो सबकी बोलती बंद हो गयी।

भारत भक्ति व भक्तो की पुण्य भूमि हैं। नेपाल और भारत की संस्कृति एक हैं।सोच एक है।दिल एक है। उसे चीन क्या कोई भी ऐसी वैसी कथित ताक़त आंतरिक रूप से कभी अलग नहीं कर सकता। कई मायनो में भारत व नेपाल एक ही हैं। एक दुसरे के सखा रहे हैं। भक्त रहे हैं। आगे भी रहेगे। कहते हैं लाली देखन मै चली, मै भी हो गयी लाल।। ज्यो ज्यो डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए।

भक्ति का विशेष रंग है, भक्ति सागर है, भक्ति रस है, भक्ति भंग है। श्रीराम तो भारत ही नहीं विश्व धरा के कण-कण में हैं ।जहाँ देखो वही है। आप महसूस करो। आपको महसूस होगा। श्रीराम की भक्ति में जो शक्ति है वो आपको कही नहीं मिलेगी। भक्ति आप

सच कहते हैं श्रीराम की महिमा अपरम्पार है। कहते है एक नास्तिक को राम नाम का जाप के लिए कहा गया था, परन्तु वो आदतन नहीं बोला, पर उपहास के तौर पर "मरा-मरा" बोलने लगा, जो बाद में स्वाभाविक तौर पर सुर बदल गया। वो "राम-राम" हो गया। अंततः उसे पूर्ण मुक्ति मिली। उसकी आत्मा तृप्त हुयी। इसे कहते हैं श्रीराम की महिमा।

किसी की भी करे, शक्ति तो मिलती ही है। भक्ति आप ईश्वर की करे या किसी अन्य की। उसका फल तो आपको मिलता ही है। ये ध्रुव सत्य है। अनुभव जन्य सत्य है। इसे कोई भी नकार नहीं सकता, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक। वैसे मैं आस्तिक हूँ परन्तु नास्तिक शब्द को नहीं मानता। क्योंकि इस संसार में कोई भी नास्तिक नहीं। जो स्वयं को घोषित करता है, वो भी नहीं। जीवन है तो आस्था है। आस्था से आस्तिकता है। जो विश्वास का ही प्रतिरूप है। जीवन व भावना एक दुसरे के पूरक है। भावना के बिना व्यक्ति नहीं, न ही ईश्वर। जिसमे भावना है, वही आस्थावादी है। इसलिए ये भी चिंतन की बात है कि इन तमाम वजह से कोई नास्तिक कैसे हो सकता हैं।

इसलिए मेरा मानना है, जो भी इस धरती पर अनिश्वरवाद की तथाकथित वकालत करते हैं वो हर वक्त किसी न किसी प्रकार से मानसिक चिंता या विकार से ग्रसित रहते हैं ।ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है।इसलिए दुनिया के सभी चिकित्सक चाहे वो किसी भी विधा से क्यों न जुड़े हो, सभी की नसीहतो में एक बात समान होती है, स्वयं के प्रति आस्था।आस्था नहीं तो जीवन अनर्थ माना जाता है। यदि आपका अस्तित्व है तो आस्था है, आस्था है तो ईश्वर है।

कुछ वर्ष पहले नेपाल विश्व का एकमात्र हिन्दू राष्ट्र कहा जाता था। नेपाल स्थित पशुपति नाथ जी का मंदिर नेपाल ही नहीं विश्व का गौरवशाली स्थान है। विश्व का हर हिन्दू, यहाँ तक कि कई दुसरे धर्मों के आम जन, नेता भी उस मंदिर में जाकर बाबा पशुपति नाथ का आशीर्वाद लेते हैं। क्या चीन या ओली साहेब में हिम्मत है कि बाबा पशुपति नाथ मंदिर के बारे ऐसी बाते कर सकते हैं? क्या चीन अपने बौद्ध विहारों को समाप्त कर सकता है? फिर वामपंथ का क्या मतलब।क्या अर्थ? जो नीतियां आम जन के खिलाफ हो, उसे अस्तित्व में रहने का कोई हक नहीं है।

भारत नेपाल के सम्बन्धो में राजीव गाँधी काल में कुछ गड़बड़ियाँ हुयी थी,जो मोदी काल में भी उसे जड़ से समाप्त नहीं किया जा सका है, जिसके लिए मोदी सरकार के कुछ मंत्री व राजनयिक भी जिम्मेदार बताये जाते हैं। अब स्थिति बिगड़ने पर रिश्तो को मज़बूत करने के तमाम उपायों पर काम शुरू हो गया है,परन्तु नेपाल को चीन के प्रभामंडल से बाहर निकालना मुश्किल तो नहीं आसान भी नहीं दिख रहा है।

आज की बदली हुयी स्थिति में नेपाल जाने-अनजाने विश्व के विस्तारवाद के महान खलनायक चीन के साथ खड़े हो गया हैं। शायद उनको पता है या नहीं, चीन ने नेपाल को कथित मदद के नाम पर कितने बड़े भू-भाग पर कब्ज़ा कर लिया है ,जो चीन का चिर परिचित स्वाभाव है चीन से नेपाल ही नहीं अव पाकिस्तान, भूटान, म्यामार के अलावा 23 देशो के प्रमुख व आम जनता त्रस्त हो चुकी हैं। वो सब अब भारत के साथ हैं। चीन के विस्तारवाद की निहित स्वार्थ वाली भावनाओ के तहत विश्व के ज्यादातर विकसित देश भारत के साथ खड़े हो गए हैं।

विश्व को समझ में आ चुका है कि चीन और भारत की तुलना में भारत ज्यादा संस्कारी, नैतिक व विश्वनीय देश हैं।चीन के घोर अमानवीय कोरोना आक्रमण की वजह से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, कनाडा, रूस सहित कई देश चीन के घोर भारत के साथ खड़े हो गए हैं। चीन विस्तारवाद के आरोपों से तिलमिलाया है। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने चीन के खिलाफ विस्तारवादी होने का आरोप लगाया तो चीन ने फौरी तौर पर उसका खंडन किया, लेकिन अपनी ओछी हरकतों से बाज़ नहीं आया। इसलिए चीन भारत के पडोसी देशो को भारत के खिलाफ भडकाना शुरू किया है, लेकिन शायद चीन फिर से एक साथ कई गलतियाँ कर रहा है। चीन ने इरान को भी भड़काने की कोशिशे की हैं। भारत सरकार ने चीन को जहाँ हजारो करोड़ के प्रोजेक्ट से बाहर का रास्ता दिखाया है तो चीन ने भी इरान के चाबहार प्रोजेक्ट से बाहर करने पर काम कर रहा है।

कहते हैं चोर चोरी से जाये, परन्तु हेरा-फेरी से न जाये, वही हाल चीन का हैं। लेकिब अब चीन कुछ भी कर ले, वो अब चारो तरफ से घिर चुका है। चाहे वो प्रधानमंत्री श्री ओली जैसे कमजोर नेता को भारत के खिलाफ उकसाने की कोशिश करे या पाकिस्तान जैसे नापाक इमरान खान को, फिर भी भारत अब आगे बढ़ता ही रहेगा,क्योकि भारत का मूलभूत नीति व सिद्धांत है –सत्य, अहिंसा और परस्पर भाई चारा के साथ वसुधैव कुटुम्बकम!

सच यह है कि सरकारों के स्तर पर रिश्ते खराब करने को उतारू ओली इसके जरिये लोगों के स्तर पर भी दुराव और अलगाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह ऐसे समय में किया है जब भारत में राम मंदिर बनाए जाने का फैसला समूचे दक्षिण एशिया में चर्चा का विषय है। #

भारत

वैश्विक अगुआ!

कोरोना महामारी के पश्चात भारत के सामने अवसर के दरवाजे खुल रहे हैं। इस अवसर को भुनाकर भारत स्वयं को दुनिया के लिए एक रोल मॉडल और प्रेरणा के रूप में स्थापित कर सकता है।

श्रीराजेश

नियति कभी-कभी उस मार्ग पर चलने के लिए बाध्य कर देती है, जिसके बारे में हम आप न तो पहले से तैयार होते हैं और ना ही उसके लिए हमारी कोई योजना होती है। परंतु किसी व्यक्ति, समाज या देश के लिए ऐसे मौके अनायास ही आ जाते हैं, जिसे एक अवसर की तरह लेकर नजीर गढ़ना संभव हो जाता है। आज भारत के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। एक प्रकार से भारत के समक्ष इस तरह की चुनौतियां बीते दिनों में दरपेश हुई हैं, जिसके लिए भारत तैयार नहीं था। बावजूद इसके इसने उन चुनौतियों को बड़ी सुझबूझ से पार किया। यह देख कर वैश्विक समुदाय भारत की ओर एक आशा भरी नजरों से देख रहा है।

बीते दिनों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा भी कि वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार दुनिया वैश्विक मंदी में आ गई है और दुनिया की अर्थव्यवस्था नकारात्मकता की ओर बढ़ रही है, ऐसे में भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बांग्लादेश जैसे विकासशील देशों के मन में भारत को लेकर ऐसी उम्मीदें भारत को सकारात्मक उर्जा से भरता है। हालांकि भारत भी विकासशील देशों के समूह में ही है, भारत में भी वह सारी समस्याएं है, जो विकासशील देशों की है लेकिन भारत इन समस्याओं से अपने निजी संसाधनों का मल्टीपल उपयोग कर आगे बढ़ रहा है और यह दुनिया को दिख रहा है।

अब दुनिया के सामने एक मील का पत्थर कोविड 19 की महामारी है। कोरोना पूर्व और कोरोना पश्चात के कालखंड को रेखांकित किया जा रहा है। कोरोना पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था पहले ही सुस्ती में थी, आर्थिक विकास दर लड़खड़ा रहे थे। इसके बावजूद भारत को भरोसा था कि अगले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन डॉलर की होगी। इसी विश्वास के दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका दावा किया था। लेकिन 2020 के वर्ष शुरू होते ही चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस ने दुनिया की अर्थव्यवस्था से लेकर सामाजिक व्यवस्था तक बदल कर रख दी। सभी बड़े व आर्थिक रूप से संपन्न देशों की अर्थव्यवस्था गर्त में गोते लगाने लगी और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत में संपूर्ण लॉकडाउन 24 मार्च से लेकर 7 जून तक जारी रहा। इस दीर्घावधि में सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां ठप रही। गरीब तबकों के सामने सबसे बड़ी समस्या भूख की थी तो मध्यमवर्ग के सामने रोजगार का संकट गहरा गया। इसी दौरान चीन की विस्तारवादी नीतियों की वजह से भारत-चीन की पूर्वी लद्दाख

सीमा पर गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाएं न केवल आमने-सामने हुई बल्कि एक हिंसक संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गये तो चीन के तरफ भी भारी क्षति हुई। यह स्टैंडऑफ तकरीबन दो महीने से चल रहा है, हालांकि अब जाकर चीन की सेनाएं पीछे हटना आरंभ की है लेकिन स्थिति अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं है। तो दूसरी ओर इंडो-पैसफिक और दक्षिण चीन सागर में भी तनाव बरकरार है लेकिन भारत ने जिस प्रकार पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन का काउंटर किया या फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिल कर सागर में चीन की घेराबंदी की। इसने दुनिया को भारत की क्षमताओं की ओर से ध्यान आकर्षित किया। भारत-चीन के बीच बड़े स्तर पर व्यापार है लेकिन इसमें भारत को ही व्यापारिक घाटा है। इसके बावजूद भारत ने कई ऐसे सांकेतिक कदम उठाये जिससे चीन को भारत को लेकर अपनी सोच में परिवर्तन लाने के लिए बाध्य किया। भारत सरकार द्वारा चीन 59 एप को प्रतिबंधित किया गया। हालांकि इसे लेकर यह कहा जा रहा है कि इससे भला चीन को हम क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन यह सांकेतिक कदम बड़े प्रतिफल देने के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। भारत के इस कदम ने चीन के डिजिटल सिल्क रोड पर डिजिटल स्ट्राइक की है और अब इस दिशा में विश्व के अन्य देश मसलन अमेरिका और यूरोप भी बढ़ने लगे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के आईटी प्रोफेनल्स को देसी एप बनाने का जो चैलेंज दिया है, आने वाले दिनों में इसका भी असर दिखेगा।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को जो अस्थाई सदस्यता मिली उसने भी भारत की कुटनीति की ओर दुनिया को देखने के लिए मजबूर किया। हालांकि भारत पहले भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य रह चुका है लेकिन इस बार कुल 192 मतों में से भारत को 184 मत मिले, जो भारत की वैश्विक पकड़ और स्वीकार्यता को दर्शाता है। विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष और मैनेजिंग बोर्ड के सदस्य बोर्गे ब्रेंड ने अपने एक आलेख में लिखा भी था, - 'अगर 19वीं सदी को औद्योगिकीकरण के उदय और 20वीं सदी को बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के विस्तार एवं ग्लोबलाइजेशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो 21वीं सदी को परिभाषित करने वाली विशेषता क्या हो सकती है? यह विशेषताएं हैं- प्रभावकारी और व्यापक बदलाव के साथ एक ध्रुवीयता से बहुध्रुवीयता की ओर शिफ्ट होना।'

वर्तमान में जो दिख रहा है, वह यही है कि भारत अब प्रभावकारी और व्यापक बदलाव के साथ एक ध्रुवीयता से बहुध्रुवीयता की ओर शिफ्ट हो रहा है। टेक्नोलॉजी में तरह-तरह के बदलाव के चलते चौथी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में अर्थव्यवस्था की प्रकृति और संरचना में बुनियादी परिवर्तन देखने को मिले हैं। उत्पादन के स्तर, स्थान और संरचना का एक ऐसा रिडिस्ट्रिब्यूशन हो रहा है, जिससे हमारे संगठन पहले से कहीं अधिक वैश्विक हुए हैं और आपस में जुड़े हैं। मौजूदा राजनीतिक ढांचों और संस्थानों में भरोसा कमजोर पड़ने से मानव समाज पहले से अधिक विरोधाभासी और अलग-थलग हुआ है। पर्यावरण संबंधी चुनौतियां और जलवायु संकट को लेकर पहले कभी इतनी चर्चा नहीं हुई थी। संक्षेप में कहें, तो इस नाजुक विश्व- व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए एक सुसंगत नेतृत्व व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

एक ऐसे समय में जब गंभीर भू-राजनीतिक और पारिस्थितिक चुनौतियां सामने हैं, व्यापार संबंधी तनाव बढ़ने के साथ नीतिगत अनिश्चितता ने निवेश और व्यवसायिक विश्वास में मंदी लाने का काम किया है। 2019 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के नीचे सरक कर 3.2% के स्तर पर आ गया, अगले कुछ वर्षों तक उसमें मामूली सुधार के अनुमान और

भारत के समक्ष कई तरह की चुनौतियां बीते दिनों में दरपेश हुई हैं, जिसके लिए भारत तैयार नहीं था। बावजूद इसके इसने उन चुनौतियों को बड़ी सुझबूझ से पार किया। यह देख कर वैश्विक समुदाय भारत की ओर एक आशा भरी नजरों से देख रहा है।

अगले कुछ वर्षों तक उसमें मामूली सुधार के अनुमान और मौजूदा बहुपक्षीय नियम-आधारित व्यापार प्रणाली की विश्वसनीयता घटने से स्थिति चिंताजनक नजर आ रही थी। उस आशंका को कोविड 19 महामारी ने वर्ष 2020 में सत्य साबित कर दिया।

मौजूदा बहुपक्षीय नियम-आधारित व्यापार प्रणाली की विश्वसनीयता घटने से स्थिति चिंताजनक नजर आ रही थी। उस आशंका को कोविड 19 महामारी ने वर्ष 2020 में सत्य साबित कर दिया। यह लगभग तय माना जा रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ, अनुमान से ज्यादा माइनस में जाएगा। ऐसे में गिरावट के आंकड़े घोर वैश्विक मंदी की ओर ले जा रही है।

इस प्रतिकूल माहौल में एक निर्णायक नेतृत्व और प्रभावी ग्लोबल प्रोफाइल के साथ भारत अवसर को अपने हाथों में लेने की ओर बढ़ रहा है। इसके विपरीत, दक्षिण एशिया के लिए इकोनॉमिक आउटलुक मजबूत बना हुआ है। पिछली आधी सदी में, उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं ग्लोबल आउटपुट में अपने योगदान को पहले के करीब 15% के स्तर से बढ़ाकर 50% से भी आगे ले गई हैं, यह सच है। मजबूत घरेलू मांग, निजी खपत और निवेश के सहारे दक्षिण एशिया की विकास दर 7% रहने का अनुमान था। लेकिन अब परिस्थितियां उस सोच और अध्ययन –आकलन के उलट है। ऐसे में वैश्विक मंदी के प्रभाव को कम करने और वैश्विक विकास को आगे ले जाने के लिए भारत का आत्मनिर्भर भारत मिशन बड़ी भूमिका निभा सकता है। बशर्ते कि भारत सरकार इसे जमीनी स्तर पर साकार करने के लिए पूरी गंभीरता से अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करे।

भारत के इकोनॉमिक आउटलुक का उल्लेख जरूरी है। उम्मीद की जा रही थी कि अगले कुछ वर्षों में एक बार फिर 7.5% जीडीपी ग्रोथ के अनुमान के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने वाला है, लेकिन यह अनुमान अब धाराशाई हो चुके हैं, बावजूद इसके भारत द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उठाये गये कदम उसे अन्य विकासशील देशों से कहीं बहुत आगे ले जा रहा है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अगले आधे दशक में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और अगले डेढ़ दशकों में 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने विजन को साकार करने के लिए भारत के पास मंच तैयार है। इस तरह से वह वैश्विक अर्थव्यवस्था के संकट को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

स्वैच्छिक और महत्वाकांक्षी रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी टारगेट्स के साथ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भारत की प्रतिबद्धता, पेरिस जलवायु समझौते की चर्चा में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका और इंटरनेशनल सोलर एलायंस, यह सब बताता है कि भारत पर्यावरण सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नेतृत्व देने में सक्षम है।

भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भारत एक ऐसा देश है, जहां साल भर में करीब 300 दिन जमीन पर धूप रहती है। यही कारण है कि सौर ऊर्जा के मामले में भारत का भविष्य स्वर्णिम है। पारंपरिक संसाधनों से बिजली पैदा करना दिनों-दिन महंगा होता जा रहा है। सौर ऊर्जा इसका एक ठोस विकल्प है।

प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में कहें, तो सौर ऊर्जा श्योर, प्योर और सिक्योर है। श्योर इसलिए क्योंकि सूर्य हमेशा चमकता रहेगा, प्योर इसलिए क्योंकि यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता और सिक्योर इसलिए क्योंकि ये हमारी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करता है। एक प्रकार से भारत ने नेतृत्वकारी भूमिका का आगाज कर दिया है।

भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा सौर उर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए लायी गई योजनाओं के फलस्वरूप पिछले कुछ सालों से भारत में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। लोग अपने खेतों, घरों और ऑफिस आदि जगहों पर सौर ऊर्जा से प्राप्त बिजली का प्रयोग कर रहे हैं। सरकार द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पीएम कुसुम योजना और अटल ज्योती योजना सहित कई योजनाएं चलाई जा रही

हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार, साल 2015 से 2017 के बीच सौर ऊर्जा का उत्पादन भारत में अपनी स्थापित क्षमता से 4 गुना बढ़कर 10,000 मेगावाट को पार कर गया था। यह देश में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता का 16 फीसद है। इस समय भारत में सोलर बिजली की दर न्यूनतम स्तर पर है। कुछ दिन पहले ही सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाली छह कंपनियों ने अपनी बोली में 2.36 रुपये प्रति यूनिट की दर से सोलर बिजली बेचने की पेशकश की है। ये कंपनियां 2,000 मेगावाट तक सोलर बिजली का उत्पादन करेंगी। इन छह कंपनियों में से पांच विदेशी और एक भारतीय कंपनी है। इससे पहले सौर ऊर्जा का न्यूनतम टैरिफ 2.44 रुपये प्रति यूनिट था। यह बोली मई 2017 में लगाई गई थी।

मौजूदा समय में भारतीय बाजार में चीन के सोलर उपकरणों की हिस्सेदारी 90 फीसद है। दिग्गज कारोबारी गौतम अडाणी का मानना है कि आने वाले पांच साल काफी अहम है। इस दौरान सोलर सेक्टर में चीनी कंपनियों का दबदबा पूरी तरह खत्म किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जुलाई को मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यह एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है और दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स में शामिल है। पीएम ने प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत अब स्वच्छ ऊर्जा का सबसे शानदार बाजार बन गया है और इस क्षेत्र में देश मॉडल बनकर दुनिया के सामने उभरा है।

मौजूदा समय में भारतीय बाजार में चीन के सोलर उपकरणों की हिस्सेदारी 90 फीसद है। दिग्गज कारोबारी गौतम अडाणी का मानना है कि आने वाले पांच साल काफी अहम है। इस दौरान सोलर सेक्टर में चीनी कंपनियों का दबदबा पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। सौर ऊर्जा क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत में ही सोलर उपकरणों का बड़े स्तर पर उत्पादन करने की जरूरत है। इससे देश आत्मनिर्भरता तो प्राप्त करेगा ही, साथ ही बहुत से लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।

भारत के पास एक यूनिक एडवांटेज यह भी है कि उसकी आधी आबादी वर्किंग एज ग्रुप की है। इस वर्ष के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 52वें स्थान पर पहुंचकर भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जिसने लगातार नौ वर्षों तक अपनी रैंक में सुधार किया है।

भारत ने अभी हाल ही में अंतरीक्ष कार्यक्रमों में निजी सेक्टर की भागीदारी के लिए ग्रीन सिग्नल दे कर एक और बड़ी उप्लब्धि की ओर बढ़ा है और इससे भारत के अंतरीक्ष कार्यक्रम और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसके पहले भारत ने अपने चंद्र अभियान और मिसाइल से लो-ऑर्बिट सैटेलाइट को मार गिराने में दुनिया का चौथा देश बनने जैसी सफलताएं अर्जित कर अंतरिक्ष संबंधी खोज के मामले में अपने वैश्विक कद का भी विस्तार किया है।

आज वैश्विक मानवीय प्रयासों और विकास की पहल में भारत पहले से कहीं अधिक सक्रिय है। इनमें अफगानिस्तान में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अश्गाबात एग्रीमेंट, चाबहार पोर्ट और भारत-म्यांमार-थाइलैंड हाइवे जैसे प्रोजेक्ट, लद्दाख के पर्वतीय क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास (चीन के विरोध के बावजूद) गिनाए जा सकते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत-अफ्रीका सहकारी हित के लिए अपना मजबूत विजन पेश किया है। इसके साथ ही शंघाई को-ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इंडिया-ब्राजील-साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम और ब्रिक्स ग्रुप जैसे अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों में भारत की विस्तृत भागीदारी उसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव को जाहिर करता है तो वहीं चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट से स्वयं को अलग रखने का निर्णय अलग-अलग वैश्विक पहल और मंचों पर सक्रिय रहने की भारत की इच्छा को भी दर्शाता है।

इस बात को जानते हुए कि वैश्विक शक्ति बनने की शुरुआत घर से होती है, भारत ने अपनी विकास की महत्वाकांक्षाओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, आधारभूत संरचना में अभूतपूर्व सुधार किए हैं। व्यावसायिक विनियमों को आसान करने का असर भारत में साफ तौर पर दिख रहा है। वर्ल्ड बैंक की 'व्यापार करने में आसान' की रैंकिंग में भारत की 65 स्थानों की छलांग एक बेहतर कारोबारी माहौल और निवेशकों के विश्वास को प्रदर्शित

करती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बीते दो महीनों में हमने देखा है, जब चीन से कई सारी कंपनियां अपना कारोबार समेट कर भारत में निवेश करने आईं और अभी यह प्रक्रिया जारी है।

भारत में पिछले एक दशक के दौरान स्टार्ट-अप्स कंपनियों का काफी विस्तार हुआ है, जो डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन रिटेल, एजुकेशन और सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों में नवेन्मेष कर रही हैं। भारत में एक बिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली कंपनियों की संख्या भी हर साल बढ़ी है। इसके अलावा, पिछले एक दशक में सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र में सबसे बड़े उदारीकरण को देखते हुए, सरकार ने बगैर बिजनेस सेंटर खोले, कंपनियों को भारत में ऑनलाइन सामान बेचने की अनुमति दी है। यह इस क्षेत्र की वैश्विक कंपनियों के लिए घरेलू बाजार में कारोबार के लिए बड़ा मौका लेकर आया है।

समावेशी विकास के साथ आर्थिक प्रगति भी हो, इसे सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ भारत ने सामाजिक क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति की है। यूआईए के तहत बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली के विस्तार ने सरकारी सेवाओं की डिलीवरी को सुव्यवस्थित किया है। इसने कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से संसाधनों के वितरण को स्ट्रीमलाइन किया है। एक अरब से अधिक लोगों का डेटाबेस तैयार करना बहुत बड़ी बात है।

इसके अलावा, वित्तीय समावेशी कार्यक्रम के तहत जन धन योजना के माध्यम से 300 मिलियन यानि 30 करोड़ लोगों को बैंक से जोड़ा गया है। इससे उन्हें औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर उनके लिए ऋण के साथ सरकारी सब्सिडी सीधे खाते में देने की व्यवस्था की गई। हालांकि जब यह योजना शुरू की गई तब इसे लेकर तरह –तरह के सवाल उठाये गये लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान इसके माध्यम से गरीबों तक राहत के तौर नकदी पहुंचाने में काफी सहुलियत हुई।

यहां यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए आयुष्मान भारत योजना है, इसका भी इस कोरोना काल में असर देखने को मिला। ये सभी ऐसे रिफॉर्म एजेंडा को लागू करने की भारत की क्षमता को दर्शाता है, जो विकास के लिए देश की जरूरतों के साथ-साथ वैश्विक आकांक्षाओं से तालमेल बिठाने में सक्षम है।

भारत के पास वैश्विक एजेंडा को आकार देने का एक अनूठा अवसर है। इन अवसरों को भुनाकर भारत स्वयं को दुनिया के लिए एक रोल मॉडल और प्रेरणा के रूप में स्थापित कर सकता है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत को समग्र संरचनात्मक सुधार की ओर अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए, जो अर्थव्यवस्था की स्थिरता और उसके लचीलेपन के अनुकूल हो। यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक सेवाओं और विकसित अर्थव्यवस्था वाली कनेक्टिविटी से लैस हो। यह सब कुछ ऐसा हो, जो युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के साथ गरीबी उन्मूलन में भी सहायक हो। पुनर्योजी, समावेशी और स्थायी अर्थव्यवस्था से प्रेरित नीतिगत समाधान यह सुनिश्चित करेंगे कि 10 ट्रिलियन डॉलर की लक्षित अर्थव्यवस्था, वैश्विक, राष्ट्रीय और जमीनी स्तर पर एक मजबूत भारत के साथ मेल खाता हो, जिसमें हर किसी के लिए अवसर हो।

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोरोना महामारी के पश्चात भारत के सामने अवसर के दरवाजे खुल रहे हैं। इस अवसर को भुनाकर भारत स्वयं को दुनिया के लिए एक रोल मॉडल और प्रेरणा के रूप में स्थापित कर सकता है। यह हमारे सामूहिक भविष्य के हित में है। भारत अपनी प्रभावी क्षमताओं का इस्तेमाल कर दुनिया को एक ऐसा मॉडल प्रदान कर सकता है, जिसमें वैश्विक चुनौतियों का समाधान हो।

भारत इस दिशा में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर सकता है। हालांकि इस व्यापक बदलाव के पैमाने को प्राप्त करना एक बड़ी बात होगी। लेकिन अपने वृहद् भौगोलिक और जनसांख्यिकीय स्वरूप के साथ व्यापक विविधता वाले भारत के पास वैश्विक एजेंडा को आकार देने का यह एक अनूठा अवसर है। #

भारत के पास वैश्विक एजेंडा को आकार देने का एक अनूठा अवसर है। इन अवसरों को भुनाकर भारत स्वयं को दुनिया के लिए एक रोल मॉडल और प्रेरणा के रूप में स्थापित कर सकता है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत को समग्र संरचनात्मक सुधार की ओर अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए।

मध्यप्रदेश: अमानवीय सोच से कब मिलेगी राहत ?

ट्राइब वॉइस नेटवर्क

मध्यप्रदेश के गुना में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से जुड़े एक मामले में कानूनी कार्रवाई के नाम पर पुलिस जिस तरह से बेलगाम हुई, उसने कानून और मानवीयता की सभी हदें तोड़ दीं। साफ है, कानून के रखवालों को चाहे जितने नियमों के पाठ पढ़ाए जाएं, लाचारों के सामने आक्रामकता दिखाने से वे बाज नहीं आते। गुना जिले के जगनपुर चक में मॉडल महाविद्यालयों को राजस्व विभाग ने 40 बीघा जमीन आवंटित की थी। इस जमीन पर पिछले 15 साल से गबरू पारदी नाम के आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति का कब्जा था। उसने यह जमीन राजकुमार अहिरवार को तीन लाख रुपए लेकर खेती के लिए ठेके पर दे दी थी। राजू और उसकी पत्नी सावित्री ने कर्ज लेकर इस जमीन पर हाड़-तोड़ मेहनत करके फसल उगाई। इसी समय पुलिस और राजस्व आमला जेसीबी मशीन लेकर जमीन खाली कराने के लिए पहुंच गया। राजकुमार और सावित्री

देश को आजाद हुए सात दशक हो गए लेकिन आजतक राजस्व दस्तावेजों का संधारण सही नहीं है। कंप्यूटरीकरण ने इस गड़बड़ी को और बढ़ा दिया है। विडंबना है कि पूरे देश में समूचे पुलिस तंत्र पर लगातार सवाल उठ रहे हैं लेकिन पुलिस का रवैया बदल नहीं रहा है। जिस राजस्व और पुलिस अमले ने भूमि खाली कराने के लिए गैर-कानूनी हथकंडे अपनाए, उनका इस्तेमाल किए बिना कानूनी तरीके से भी कब्जा हटाया जा सकता था।

ने फसल पकने तक खेत नहीं उजाड़ने की हाथ जोड़कर प्रार्थना की लेकिन जब जेसीबी ने फसल रौंदना शुरू कर दिया तो किसान दंपति की सभी आशाओं पर पानी फिर गया और उन्होंने झोंपड़ी से कीटनाशक दवा उठाकर पी ली। उनके चार बच्चे इस हालात को देखकर रोने-चिल्लाने लगे। तब राजकुमार का छोटा भाई शिशुपाल और उसकी पत्नी दौड़कर आए। इन निहत्थों पर पुरुष एवं महिला पुलिस ने इतनी लाठियां बरसाईं कि उनके कपड़े तक चिथड़े-चिथड़े हो गए। जब दोनों निढाल होकर खेत में पसर गए तब बेरहम पुलिस की बर्बरता थमी।

इस हृदय विदारक घटना का समाचार प्रकाशित व प्रसारित होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर व एसपी के तबादले कर दिए और छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। लेकिन इसके पहले दलित किसानों पर सरकारी काम में बाधा डालने की एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली। सरकार की ओर से न तो अभीतक इस मामले को खत्म करने का भरोसा दिया है और न ही दलितों की कोई आर्थिक मदद की घोषणा की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जरूर दलित किसान को सवा लाख रुपए की मदद की है।

इस मामले की पड़ताल से पता चलता है कि इसमें राजस्व विभाग बुनियादी तौर से दोषी है। जब जमीन पर 15 साल से कब्जा चला आ रहा था तो उसे शुरुआत में ही क्यों नहीं रोका गया? दरअसल मध्यप्रदेश में जितनी भी राजस्व और वन विभाग की जमीनों पर कब्जे कर खेती हो रही है, उनपर सुनियोजित ढंग से राजस्व और वनकर्मियों ने ही कब्जा कराया हुआ है। ये लोग बीघा के हिसाब से कब्जेधारी से खेती करने के पैसे लेते हैं। बांधों के निर्माण में जो जमीन डूब क्षेत्र में आई हुई है, उसे मुआवजा दे दिए जाने के बावजूद सिंचाई विभाग के लोग खेती के लिए ठेके पर दे रहे हैं। नदियों से अवैध रूप में रेत उत्खनन का खेल तो पूरे मध्य-प्रदेश में खुले रूप में नेता-अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत से चल रहा है। इस खनन के आए दिन समाचार भी आते रहते हैं लेकिन शासन-प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती।

देश को आजाद हुए सात दशक हो गए लेकिन आजतक राजस्व दस्तावेजों का संधारण सही नहीं है। कंप्यूटरीकरण ने इस गड़बड़ी को और बढ़ा दिया है। विडंबना है कि पूरे देश में समूचे पुलिस तंत्र पर लगातार सवाल उठ रहे हैं लेकिन पुलिस का रवैया बदल नहीं रहा है। जिस राजस्व और पुलिस अमले ने भूमि खाली कराने के लिए गैर-कानूनी हथकंडे अपनाए, उनका इस्तेमाल किए बिना कानूनी तरीके से भी कब्जा हटाया जा सकता था। लेकिन पुलिस जब लाचार व दलित फटेहालों से रूबरू होती है तो वह अक्सर बेलगाम हो जाती है। ऐसी ही घटनाओं के बरअक्स मध्य-प्रदेश भू-राजस्व संहिता और पुलिस सुधारों में बदलाव की बात उठती है लेकिन यह आवाज कुछ दिनों में ही नक्कारखाने की तूती बन रहकर दम तोड़ देती है। #

छत्तीसगढ़: गौ सेवकों को मिलेगा "गोबर-धन"

कवर स्टोरी

गाय माता और गोबर तो गुणों की खान है, हर भारतीय उनके गुणों से परिचित है, गोबर का इस्तेमाल बहुआयामी है, गोबर की गुणवत्ता किसी प्रमाण पत्र की मोहताज नहीं। सरकार की इस योजना से न केवल गौ माता सुरक्षित होंगी बल्कि ग्रामीण रोजगार के सृजन में भी सहायक होगी। वही राम वन गमन पथ लोगों की धार्मिक आस्था के साथ-साथ आवागमन, रोजगार, व्यवसाय में विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।

ट्राइब वॉइस नेटवर्क

नि मेरे देश की धरती सोना उगले-उगले हीरे मोती पुरानी फ़िल्म के इस गीत को सुन कर आज भी ह्रदय रोमांच से भर जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार के माटी पुत्र भूपेश के नेतृत्व में इस गीत को साकार करने में आगे बढ़ती नजर आ रही। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब गोबर की खरीद की जाएगी। लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये किसान पुत्र करना क्या चाहते हैं। जी हां, बात हो रही है छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल की।

जब भारत में कोरोना महामारी का आगाज भी नहीं हुआ था तो मुख्यमंत्री ने सम्पूर्ण लॉक डाउन के कठोर निर्णय से सभी को अचंभित कर दिया था, उसी का परिणाम है कि जब देश में एक दिन में हजारों में मरीजों की वृद्धि हो रही है छत्तीसगढ़ में मरीजों की वृद्धि दर अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत कम है। कोरोना काल में ही मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने ये अनुमान लगा लिया था कि जब कोरोना महामारी का मध्यकाल आएगा, लोग रोजगार के लिए तरस जायंगे, दो वक्त की रोटी उनके लिए मजबूरी बन जायेगी। दूरगामी सोच का परिणाम रहा कि मनरेगा में पिछले 100 दिनों में रोजगार देने वाला देश का अग्रणी राज्य छत्तीसगढ़ रहा। राशन दुकान से सभी को जिनके पास राशनकार्ड नहीं है उन्हें भी आवश्यक राशन उपलब्ध करवाया। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषण आहार घर-घर पहुंचाया गया। मध्यान भोजन का तीन माह का राशन छात्रों को दिया गया। व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए व्यवसाइयों को निश्चित परिधि में छूट दी गई, बसों के टैक्स माफ किये गए, उद्योग को पुनः प्रारंभ के लिए क्रमबद्ध कार्ययोजना को अमली जामा दिया गया, स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया गया और प्रदेश के लोगों को भूख की त्रासदी से बचाने में मुख्यमंत्री कामयाब रहे। हजारों मजदूरों को ट्रेन बस से अन्य राज्यों से लाया गया। उनके आवास भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था प्रदेश सरकार ने व्यवस्थित तरीके से की।

प्रदेश के मुखिया किसान पुत्र ने माटी की सेवा करने वालो के दर्द को समझा और सरकार बनते के साथ उन्होंने अपने वादे को निभाते हुए किसानों का कर्ज माफ कर दिया। मुख्यमंत्री इस बात से भिज्ञ है कि यदि किसान समृद्ध, स्वस्थ और उत्साह में होगा तो धरती माँ सोना उगलेगी। सरकार द्वारा गोबर खरीदी का निर्णय और भविष्य में मुफ्त चारा देने की योजना आज बहुतों की समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो अनर्गल भी बोल रहे हैं, ऐसे ही लोगों ने प्रदेश में जब सम्पूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया गया था तब भी प्रश्न चिन्ह लगाया था शायद वे आज भूल गए कि जो लोग गो माता के असली उपासक होने का दावा करते थे और स्वदेशी के तथाकथित ठेकेदार थे।आज जब कोई मुख्यमंत्री गऊ माता की सेवा करने उतरा तो आपके बोल अनर्गल क्यों हो गए।

गऊ माता और श्री राम के तथाकथितभक्त की समझ में आज नहीं आ रहा कि सरकार की गोबर खरीदी योजना और भविष्य में मुफ्त चारा योजना और राम वन गमन पथ निर्माण का विरोध करे या समर्थन। क्योंकि जो कार्य उनको जनता द्वारा दिये गए 15 साल में वो नहीं कर पाए वो कार्य नई सरकार कार्यकाल के दो साल के अंदर कैसे अग्रसर होती नजर आ रही है।

गाय माता और गोबर तो गुणों की खान है, हर भारतीय उनके गुणों से परिचित है, गोबर का इस्तेमाल बहुआयामी है, गोबर की गुणवत्ता किसी प्रमाण पत्र की मोहताज नहीं। सरकार की इस योजना से न केवल गौ माता सुरक्षित होंगी ग्रामीण रोजगार के सृजन में भी सहायक होगी। वही राम वन गमन पथ लोगों की धार्मिक आस्था के साथ-साथ आवागमन, रोजगार, व्यवसाय में विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, निश्चित ही सरकार की हर योजना की तरह इस योजना के परिणाम भी सकारात्मक ही आयंगे। निश्चित ही प्रदेश छत्तीसगढ़ में पुरानी फ़िल्म का गीत साकार होगा मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती।

छत्तीसगढ़ में अब गाय-भैंस पालने वालों के दिन फिरने वाले हैं क्योंकि राज्य सरकार ने अब किसानों से डेढ़ रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर ख़रीदने का फ़ैसला किया है। गोबर ख़रीदने के लिये हाल ही में राज्य सरकार ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया था, जिसने गोबर ख़रीदी की दर पर अंतिम मुहर लगा दी है।राज्य के कृषि मंत्री और समिति के अध्यक्ष रवींद्र चौबे ने इसकी घोषणा करते हुए कहा, "हमने डेढ़ रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर ख़रीदने की अनुशंसा की है। इसे मंत्रिमंडल में पेश किया जायेगा। हमने गोबर ख़रीदने की पूरी तैयारी कर ली है और गांवों में 21 जुलाई, हरेली त्यौहार के दिन से गोबर ख़रीदी की शुरुआत की जायेगी।" राज्य सरकार ने "गोधन न्याय योजना" के नाम से गोबर ख़रीदने का फ़ैसला पिछले महीने लिया था। लेकिन गोबर ख़रीदी की दर क्या हो, इसे लेकर संशय था। इसके अलावा गोबर प्रबंधन को लेकर भी कई सवाल थे। इसके बाद गोबर ख़रीदने के लिये

मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई गई थी।

इस योजना के बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था कि पशु रखने के काम को व्यावसायिक रूप से फायदेमंद बनाने, सड़कों पर आवारा पशु की समस्या से निपटने और पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज़ से योजना महत्वपूर्ण है। हालांकि सरकार ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो एक दिन में कुल कितना गोबर खरीदेगी और इस पूरी योजना में कुल कितना खर्च होगा और ये खर्च आएगा कहां से। गोबर की ख़रीदी को लेकर राज्य के मुख्य सचिव आरपी मंडल की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गई है। ये समिति गोबर ख़रीदी के वित्तीय प्रबंधन पर रिपोर्ट तैयार कर रही है।

राज्य सरकार का दावा है कि गोबर ख़रीदी की पूरी की पूरी कार्य योजना बेहद महत्वाकांक्षी और ग्रामीण अर्थव्यव्था को मज़बूती प्रदान करने वाली साबित होगी। कृषि मंत्री रवींद्र चौबे का कहना है कि गांवों में बनाई गई गौठान समितियों अथवा महिला स्व-सहायता समूह द्वारा घर-घर जाकर गोबर एकत्र किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीणों का विशेष ख़रीदी कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें हर दिन के गोबर की मात्रा और भुगतान का विवरण दर्ज़ होगा। मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने किसानों और पशुपालकों से खरीदे गए गोबर के एवज़ में हर पखवाड़े यानी हर पंद्रह दिन में एक बार भुगतान किए जाने की बात कही है।नगरीय इलाक़ों में गोबर की ख़रीदी का काम नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा तथा जंगल के इलाक़े में वन प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाएगा।

अधिकारियों का कहना है कि फ़िलहाल, राज्य में पांच हज़ार गौठानों के ज़रिए गोबर ख़रीदी और खाद निर्माण का फ़ैसला लिया गया है और इसमें लगभग साढ़े चार लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा।भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के 2019 के आरंभिक आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में लगभग 1,11,58,676 गाय और भैंस हैं और पशु वैज्ञानिकों की मानें तो औसतन एक गाय-भैंस प्रतिदिन लगभग 10 किलो गोबर देती है। लेकिन गली-मोहल्लों में अभी से गोबर के गणित की चर्चा शुरु हो गई है। किसान भी

गोबर का गणित हल करने में जुट गये हैं। धमतरी के किसान राजेश देवांगन कहते हैं, "अगर राज्य सरकार एक करोड़ गाय-भैंस का गोबर भी ख़रीदती है तो दस किलो के हिसाब से भी हर दिन लगभग 10 करोड़ किलो गोबर ख़रीदना होगा, जिसकी क़ीमत 15 करोड़ रूपये होगी। इस हिसाब से महीने के 450 करोड़ रूपये और साल भर में 5400 करोड़ रूपये का भुगतान सरकार को केवल गोबर के लिये ही करना होगा।"

लेकिन विपक्ष को संशय है कि राज्य सरकार अपनी इस योजना को अमली जामा पहना पाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जितने भी वादे किये थे, उसमें से एक भी वादा सरकार पूरा नहीं कर पाई। रमन सिंह कहते हैं, "धान तो ख़रीद नहीं सके। एक-एक दाना धान ख़रीदने की बात थी, किसानों को बोनस देने की भी बात थी। दो साल का बोनस अभी भी बचा हुआ है। जब बोनस की बात होती है, तो नवयुवकों की बेरोज़गारी भत्ता की बात भी होती है। लेकिन सरकार कहती है कि उसके पास पैसा नहीं है। सरकार गोबर भी ख़रीदे और धान भी ख़रीदे लेकिन इन बातों को लेकर बहानेबाजी नहीं होनी चाहिये।"

गाय, गोबर और गोमूत्र जैसे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में दिखते रहे हैं।लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू किया है। "छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी" (छत्तीसगढ़ के चार चिन्ह- नाला, गोवंश, दिन फिरने का वक्त और घर का साथ की ज़मीन) - के नारे के साथ सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी ने जलप्रबंधन, गोधन, घरों से निकलने वाले जैविक कचरे से खाद निर्माण और घर से सटी हुई ज़मीन पर सब्जी-भाजी उगाने की अपनी योजना को पहले दिन से ही लागू करने की घोषणा की थी। सत्ता में आने के बाद से राज्य सरकार गाय और बैलों को एक जगह रखने के लिये गांव-गांव में गौठान का निर्माण कर रही है। अधिकारियों के अनुसार अब तक प्रदेश में 2200 गौठान बनाये जा चुके हैं, इसके अलावा 2800 गौठान जल्दी ही तैयार हो जायेंगे। सरकार का दावा है कि सभी ज़िलों के गौठानों में महिला समूहों द्वारा वर्मी कम्पोस्ट खाद भी बनाया जा रहा है।

अब सरकार द्वारा निर्धारित दर पर किसानों एवं पशुपालकों से गोबर की ख़रीदी की जाएगी, जिससे बड़े पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट खाद का उत्पादन किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि देश में पहली बार गोबर की ख़रीदी करने वाला छत्तीसगढ़ सरकार का यह फ़ैसला एक तरफ़ जहां सड़कों पर घूमने वाले पशुओं की रोकथाम करेगा, वहीं इस गोबर से बनने वाले खाद से राज्य में जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा।

उनका कहना है कि इसके अलावा पशुपालकों को भी लाभ होगा और गांवों में रोज़गार और अतिरिक्त आय के अवसर भी बढ़ेंगे। भूपेश बघेल ने आने वाले दिनों में गोमूत्र ख़रीदी के भी संकेत दिये हैं। उनका कहना है कि सरकार के इस फ़ैसले से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को लाभ होगा। #

अगस्त क्रांति : जिसने हिला दी अंग्रेजी हुकूमत की जड़े

"अगस्त क्रांति आंदोलन के दौरान मुंबई में नौसेना ने भी विद्रोह किया जिससे अंग्रेजी शासकों की नींद उड़ गयी। यूरोप में अपने देश में द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका झेलते हुए अंग्रेजों की समझ में आ गया कि अब भारत में अंग्रेजी हुकूमत के दिन ढ़ल गए हैं। "

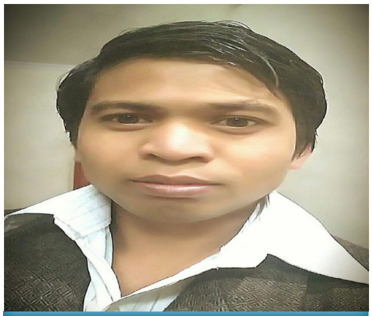

संदीप कुमार सिंह

भारत के लम्बे स्वतंत्रता आंदोलन में अगस्त क्रांति ऐसा निर्णायक दौर था जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को स्पष्ट संकेत दिया कि उपनिवेशवाद का युग अब अपनी अंतिम सांसे गिन रहा है।

अगस्त क्रांति का सूत्रपात महात्मा गाँधी द्वारा "अंग्रेजों भारत छोड़ो" आन्दोलन के साथ हुआ। देखते ही देखते यह एक जन आंदोलन बन गया जिसमें कई नए-नए शक्तिपुंज उभर कर सामने आए। महात्मा गाँधी समेत कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं को जेल में डालकर अंग्रेजों ने अनजाने में ही नई पीढ़ी के हाथ में स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर सौप दी थी। इस युवा पीढ़ी के इरादे व तेवर और भी अधिक आक्रामक थे। जेल में कैद नेताओं की अपील पर नवयुवक और भी उत्साहित हो चले थे।

अगस्त क्रांति के दौरान जो महत्वपूर्ण युवा नेता उभरकर सामने आए उनमें **जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन तथा अरुणा आसिफ अली** थे। इनको वैचारिक और सैद्धांतिक प्रेरणा देने वालों में **आचार्य नरेन्द्र देव** और **डॉ. सम्पूर्णानंद** प्रमुख थे।

यह युवा नेतागण और उनके प्रेरणास्त्रोत रहे कांग्रेसी बुजुर्ग नेताओं का पूरा सम्मान करते थे, पर उनके सामने आने और अगस्त क्रांति का नेतृत्व करने के कारण स्वाधीनता संग्राम आंदोलन के नेतृत्व में युवा वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो गई तथा आंदोलन का स्वरूप भी बदला। जैसा स्वाभाविक था नेहरू इस वर्ग के लिए आकर्षण का केन्द्र थे। **नेहरू स्वयं महात्मा गाँधी का बहुत आदर करते थे, लेकिन इस नए युवा वर्ग के समर्थन के साथ वर्ष 1942 के बाद देश में सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक नेता नेहरू ही थे, न की महात्मा गाँधी थे, न ही सरदार पटेल थे और न ही मौलाना आजाद थे।**

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में समतावादी और समाजवादी प्रशासन की परिकल्पना अगस्त क्रांति का ही परिणाम थी। प्रमाणित पुस्तक "एशियन ड्रामा" के लेखक गुन्नार मिर्डल के अनुसार भारत के विभाजन की प्रक्रिया तेज करने में "समाजवादी शोर" का भी हाथ था। **मुस्लिम सामंतों को यह चिंता सताने लगी, कि यदि भारत में समाजवाद आ गया तो फिर उनका क्या होगा। इसलिए उन्होंने पृथक मुस्लिम राज्य की मांग को बल दिया, जिसके परिणामस्वरुप पाकिस्तान बनने का रास्ता सुगम हो गया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवाद एक खतरा था। इसलिए उन्होंने भी मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया।**

अगस्त क्रांति आंदोलन के दौरान मुंबई में नौसेना ने भी विद्रोह किया जिससे अंग्रेजी शासकों की नींद उड़ गयी। यूरोप में अपने देश में द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका झेलते हुए अंग्रेजों की समझ में आ गया कि अब भारत में अंग्रेजी हुकूमत के दिन ढ़ल गए हैं। #

अगस्त क्रांति का सूत्रपात महात्मा गाँधी द्वारा "अंग्रेजों भारत छोड़ो" आन्दोलन के साथ हुआ। देखते ही देखते यह एक जन आंदोलन बन गया जिसमें कई नए-नए शक्तिपुंज उभर कर सामने आए। महात्मा गाँधी समेत कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं को जेल में डालकर अंग्रेजों ने अनजाने में नई पीढ़ी के हाथ में स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर सौप दी थी।

क्या समाज को एनकाउंटर पसंद है ?

ट्राइब वॉइस नेटवर्क

आम आदमी के सामने सवाल यह है कि आज वह किस पर भरोसा करे। न्याय देने का काम अदालतों का है। वहां हत्या जैसे जघन्य तो छोड़िए सामान्य अपराधिक मामले भी दस बीस या तीस साल तक खिंचते चले जाते हैं और आरोपी जमानत पर अपना सारा पारिवारिक व सामाजिक जीवन बिताते चले जाते हैं। वह भी सम्मान के साथ। बलात्कारी तो जमानत पर रिहा होने के बाद फिर से दो तीन बलात्कार करते हैं, फिर जेल जाते हैं और फिर जमानत पर रिहा होकर समाज में अपना जीवन जीते रहते हैं। ये लोग अपने आसपास की युवतियों व बच्चियों को हमेशा ही संत्रास में डाले रहते हैं। और विकास दुबे जैसे लोगों के तो अपराध दर्ज तक नहीं होते। हो भी जांए तो अदालत तक नहीं पहुंचते। पहुंच जांए तो गवाह नहीं मिलते, मिल जांए तो एक दो गवाही के बाद मुकर जाते हैं। दुबे जैसे लोग पाले भले ही राजनेताओं द्वारा जाते हैं लेकिन उनके व अपने हितों की आपूर्ति वे आमजन के हितों को ताक पर रखकर ही करते हैं। उनके लिए अपने स्वार्थ को साधने के लिए जिस किसी को भी मौत के घाट उतारना पड़े वे उतार देते हैं। क्योंकि इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहता है, ऐसे में पुलिस भी उनके खिलाफ कुछ करने को तैयार नहीं होती। कानून की नियामक, रक्षक व संरक्षक जब तीनों ही संस्थाएं उसे निराश कर रही हैं, और वह भी एक लंबे समय से, तो एनकाउंटर में वह न्याय देख पा रहा है तो इसमें उसका कसूर भी क्या है। उसे तो लगता है कि 'चलो पाप का अंत हुआ'। लेकिन कौन जानता है कि कल को ऐसे पापों का अंत करने के लिए वह खुद भी यही तरीका इस्तेमाल करने लगे। न्याय जब सड़क पर ही होना है तो फिर चाहे वह पुलिस करे या पीड़ित खुद, इससे क्या फर्क पड़ता है। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से उनकी अपराधियों का सफाया नीति के तहत लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं।

विकास दुबे का जो एनकाउंटर दस जुलाई को पुलिस ने किया, हिसाब से उसे तो 2001 में ही हो जाना चाहिए था जब उसने भाजपा के राज्यमंत्री संतोष शुक्ला की शिवली थाने में खुलेआम गोली मार कर हत्या की थी। मगर तब थाने में मौजूद एक भी सिपाही/अधिकारी ने चूं तक नहीं की और बाद में विकास इसलिए छूट गया कि शुक्ला के अपने स्टाफ ने ही विकास के पक्ष में बयान दे दिए। जब वह 2001 में ही इतना ताकतवर था कि भाजपा जैसी पार्टी के मंत्री की हत्या के बावजूद उसी के स्टाफ को डरा-धमका कर अपने पक्ष में कर लिया तो साचिए कि बीते 20 साल में उसने कितनी राजनीतिक व आर्थिक ताकत बटोरी होगी। उसकी पत्नी व खुद दोनों ही जिला स्तर के चुनाव जीत चुके थे और अब पत्नी विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। इसलिए पुलिस का उसके साथ होना कोई खास बात नहीं। राजनेता पुलिस को अपना काम करने ही कहां देते

हैं। और खुद अधिकारी राजनेताओं की जी हजूरी करते हैं ताकि उनकी अपनी नौकरी न केवल बची रहे, उनके अपने आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक हितों का लगातार विकास होता रहे।

तो जहां न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठ गया हो और राजनीति व प्रशासन और पुलिस की अपराधियों से साठ-गांठ लगातार मजबूत होती जा रही हो, तब लोकतंत्र का क्या होगा। ऐसे अपराधिक तत्वों से संचालित राजनीति व प्रशासन से समाज का स्वरूप क्या बनेगा। राजनीति का स्वरूप क्या बनेगा। भारत में 1960 के बाद से राजनीति का अपराधीकरण शुरू हुआ था और 1985 के बाद से अपराध के राजनीतिकरण ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। वहां से आज हम यहां तक पहुंच गए हैं कि आम समाज संवैधानिक संस्थाओं से न्याय पाने की बजाए सड़क पर पुलिस द्वारा, तमाम नियमों का उल्लंघन कर किए जा रहे 'न्याय' पर खुशी जता रहा है। तो यह बताता है कि अब हम शासन प्रशासन व अपराधों की ऐसी अंधी गली में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां हर कोई अपने हिसाब से न्याय के नाम पर दूसरे का गला काटने को तैयार होगा। और कोई उसे गलत भी नहीं मानेगा। समाज में अपराधों पर लगातार बन रही फिल्में और उनकी बढ़ती लोकप्रियता भी इसका संकेत है। विनोद दुबे पर उसके एनकाउंटर के दूसरे दिन ही फिल्म बनाने की घोषणा भी यही बताती है। एनकाउंटर से विनोद दुबे और भारतीय राजनीति व पुलिस प्रशासन की जिस अपराधिक गंदगी पर पर्दा डाल दिया गया है उसे आम आदमी फिल्मी पर्दे पर देखकर सच को जान लेने का गुमान करेगा।

ऐसा नही है कि राजनीति के अपराधीकरण पर चिंता नहीं जताई गई। जब से राजनीति में अपराधियों को टिकट दिए जाने लगे तब से चिंता के स्वर भी उठने लगे। उस समय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाली प्रेस में भी और खुद राजनीतिक दलों के बीच भी। पर पहली बार इसका स्पष्ट घिनौना चेहरा वोहरा समिति की रिपोर्ट से सामने आया जिसमें बताया था कि कैसे 1993 के बंबई विस्फोट अपराधिक तत्वों, राजनीति व प्रशासन के मेलजोल का नतीजा थे। उसके बाद 2 मई, 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हर उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्र में अपनी शिक्षा, आय व अपराधिक इतिहास के बारे में घोषणा करनी होगी। आय व शिक्षा तो बताई जाने लगी पर अपराधिक रिकॉर्ड कोई नहीं बताता था।

2005 में सूचना के अधिकार के तहत लोगों को उम्मीदवारों के बारे में जानकारी लेने का अधिकार मिला। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पाए अपराधियों को चुनाव लड़ने की छूट समाप्त कर दी। 2014 में अदालतों से कहा कि वे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चल रहे अपराधिक मामलों का एक साल के भीतर निपटारा करें। 2017 में केंद्र से जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चल रहे मामलों को जल्द निपटाने के लिए विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान करने के लिए कहा। पर उसने ऐसा कुछ किया नहीं। 2018 में सभी राजनीतिक दलों को आदेश दिया कि वे अपने निर्वाचित सदस्यों के खिलाफ चल रहे सभी मामलों को प्रकाशित करें।

पर जब इस आदेश का भी पालन नहीं किया गया तो 13 फरवरी, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर सभी दलों को निर्देश दिया कि वे अगर अपराधिक मामले के किसी आरोपी को टिकट देती हैं तो उन्हें उसका अपराधिक इतिहास भी बताना होगा। इसके साथ ही वे कारण भी बताने होंगे जिनकी वजह से उन्होंने किसी साफ छवि वाले व्यक्ति को टिकट न देकर अपराध में फंसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया। यह सारी जानकारी उन्हें अखबारों में छपवानी होगी और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी डालनी होगी।

यहां यह बताना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से अधिकतर आदेश गैरसरकारी संगठनों की अपील पर दिए हैं। राजनीतिक दलों में खुद कभी भी कोई आगे नहीं आया। उन्हें इसकी परवाह भी नहीं क्योंकि अपराधी तत्व, जिन्हें वे पालते हैं, उनका धन व बाहुबल उनकी जीत और सत्ता को सुनिश्चित करता है। यही कारण है कि लोकसभा के हर चुनाव में अपराधिक सांसदों की संख्या बढ़ती ही गई है। 2004 में लोकसभा में 24 प्रतिशत, 2009 में 30 प्रतिशत, 2014 में 34 प्रतिशत व 2019 में 43 प्रतिशत सांसद ऐसे थे जिन पर कोई न कोई अपराधिक मुकदमा चल रहा था। इनमें से 29 प्रतिशत पर तो जघन्य अपराधों के आरोप थे। अधिकतर विधानसभाओं में भी ऐसे उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती ही गई है। कारण हर पार्टी के लिए ये उनके 'जिताऊ चेहरे' होते हैं। अपना यह फैसला देते हुए जस्टिस आर एफ नारीमन ने बेहद दुख के साथ कहा था कि कोई भी पार्टी कभी यह नहीं बताती कि वह आराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार क्यों चुनती है। #

अंग्रेजी सीखने के आसान टिप्स

अजय सिंह

"भारत वर्ष में अंग्रेजी भाषा आमतौर बोलचाल की भाषा का पर्याय नहीं रही है। इसलिए हमें अपनी मातृभाषा हिंदी के सामान अनुकूल वातावरण न होने के कारण अंग्रेजी सीखना बड़ा ही दूभर कार्य लगता है। जिन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सिर्फ हिंदी भाषा में मिलती है, उनके लिए अंग्रेजी सीखना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं होता है।"

टिप्स न. 1

अंग्रेजी सीखने के लिए कोचिंग या फिर ऑनलाइन फ्लेटफार्म चुने : अंग्रेजी सीखने के लिए आप किसी कोचिंग सेंटर की सहायता ले सकते हैं। लेकिन आमतौर पर यह तरीका हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। ऐसे में ऑनलाइन के माध्यम से भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। कई अंग्रेजी सिखाने वाले वेवसाइट्स उपलब्ध हैं जो वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी सिखाते हैं। यदि फिर भी कोई समस्या हो तो यूट्यूब एक बेहतर विकल्पके रुप में मौजूद क्योंकि वहां कई अंग्रेजी सिखाने वाले चैनल्स उपलब्ध हैं जिनका आप अपनी सुविधा व समक्ष के अनुसार चयन कर सकते हैं और अंग्रेजी सीख सकते हैं।

टिप्स न. 2

अंग्रेजी सुनने व बोलने के लिए वातावरण बनाना: अपने घर-परिवार में अपने भाई-बहनों और दोस्तों के साथ आपसी बातचीत में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि इस दौरान कहीं कुछ गलती भी हो जाती है तो उसकी परवाह किए बिना मातृभाषा हिंदी की ही तरह बोलते रहना चाहिए। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि अंग्रेजी सीखने के लिए अनुकूलित होते जा रहे हैं।

टिप्स न. 3

अंग्रेजी सुनने व समझने की आदत विकसित करना: आपको भाषा बार-बार सुनने की आदत डालनी होगी। जब आप बार-बार भाषा को किसी टीवी प्रोग्राम या वीडियो में सुनेंगे तो आपकी आंग्रेजी भाषा की समझ विकसित होती जाएगी और आप धीरे-धीरे भाषा में निपुण होते जाएंगे।

टिप्स न. 4

अंग्रेजी समाचारपत्रों को पढ़ने की आदत डालना : हर दिन अंग्रेजी समाचारपत्र पढ़ना चाहिए और उसे एक कॉपी लिखने की भी आदत डालनी चाहिए। जिससे आप अंग्रेजी शब्दों को सीखेगे और आपको याद भी आसानी होने लगेगा। ऐसा जब निरंतर करने लगेंगे तो अंग्रेजी ज्ञान तो बढ़ेगा ही साथ ही साथ आपके लिखने की कला भी विकसित होगी।

टिप्स न. 5

अंग्रेजी टीवी कार्यक्रमों में बोले गए शब्दों की नकल करना: किसी पसंदीदा अंग्रेजी टीवी प्रोग्राम का चयन कीजिए और फिर उसे हर दिन देखिए। इससे भाषा को बोलने की कला व उसका विस्तार आपको समझ में आन लगेगा। साथ ही यह भी प्रयास करें की प्रोग्राम देखते समय टीवी कलाकार द्वारा बोले गए शब्दों की नकल करने की आदत भी डाले। जिससे अंग्रेजी बोलते समय होने वाली झिझक भी दूर होगी।

टिप्स न. 6

व्याकरण ज्ञान बढ़ाना चाहिए : किसी भी भाषा में व्याकरण अनिवार्य हिस्सा होता है लेकिन उसे हावी नहीं होने देना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हर भाषा की नींव उसके शब्द होते हैं और इन शब्दों से ही वाक्य बनते है। लेकिन इन शब्दों का मेल सही है या गलत इसे जानने व समझने के लिए किसी डिक्सनरी तथा व्याकरण बुक का सहारा लेना चाहिए। साथ ही उसका अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। तभी हम अंग्रेजी को सही मायने में सीख सकेंगे। #

जहाँ जैसा मिजाज व माहौल वहाँ वैसा पहनावा

प्रियंका

"कभी-कभी तो बड़ी उलझन होती है कि किस मौके पर किस रंग के कपड़े पहने जाएं। लेकिन यदि आपको पहले से ही रंगों के बारे में थोड़ी बहुत समझ है तो आपको कुछ खास परेशानी नहीं होगी। क्योंकि यदि आप थोड़ी-सी सूझबूझ और अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करेंगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा रंग किस मौसम में सही रहेगा।"

मानव जीवन में रगों का अपना एक खास ही महत्त्व है। यदि हम कहें कि हमारा पूरा मानव व्यक्तित्व ही रंगों से भरा पड़ा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे चेहरे का रंग, बालों का रंग, आंखों का रंग और वेशभूषा रंग इत्यादि, यह सभी आपस मे मिलकर एक विशेष व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इसके अलावा रंगों का संबंध हमारी संवेगात्मक अभिव्यक्ति से भी होता है। हम जिस रंग को पसन्द करते हैं उस रंग के अनुसार ही हमारी रचनात्मक सोच, इच्छाएं तथा मनोवृत्तियां उभर कर सामने आती हैं।

हम कपड़े पहनने के लिए जिन रंगों का चयन करते हैं, उन रंगों का असर न सिर्फ आपके अपने व्यक्तित्व पर होता है, बल्कि वह दूसरों पर भी गहरा प्रभाव छोड़ता है। कभी-कभी तो बड़ी उलझन होती है कि किस मौके पर किस रंग के कपड़े पहने जाएं। लेकिन यदि आपको पहले से ही रंगों के बारे में थोड़ी बहुत समझ है तो आपको कुछ खास परेशानी नहीं होगी। क्योंकि यदि आप थोड़ी-सी सूझबूझ और अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करेंगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा रंग किस मौसम में सही रहेगा।

जाड़ो के महीनों में आपको अपनी आल्मारी में गहरे नीले, हरे, बैगनी, नारंगी, अम्बर और गहरी गुलाबी रंग के कपड़ों का संग्रह रखना चाहिए। इन महीनों में रात के कपड़ो के लिए मलबारी सिल्क, टसर मंसूर सिल्क, रॉ सिल्क मूगों सिल्क आदि में से किसी भी रंग का चुनाव करना चाहिए।

ज्यादातर परस्पर विरोधी रंगों में साडियां ट्यूब लाइट्स में आपके सौन्दर्य को दुगना कर देती है। घूमने, सैर-सपाट या मिलने के लिए सादी या छपी सिल्क की साड़ियां ही बेहतर होती हैं। दिन के समय हैण्डलूम की सादी तथा वायल की छपी धौतियां सही लगती हैं। यदि आपके पास वायल को हल्के रंग की साड़ी है और आप उसे जाड़ों में पहनना चाहती है तो उसके साथ गहरे रंग का ब्लाउज और कार्डीगन पहनें। किसी सादी साड़ी में गहरे रंग का मैंचिग पल्ला और बार्डर लगा लें।

गर्मी में हल्के, सोफियाने और सर्दी में गहरे, चटक रंग अच्छे लगते हैं। पर यह इस बात पर निर्भर करता है कि वस्त्र किस ढंग से पहने गए हैं। गर्मियों में भी यदि चटक रंग कायदे के साथ और समय को ध्यान में रख कर पहने जाएं तो वे हल्के रंगों से भी ज्यादा प्रभावित करते हैं। गर्मी में हल्के, सोफियाने और सर्दी में गहर, चटक रंग अच्छे लगते हैं। पर अधिकतर यह इस बात पर निर्भर करता है कि वस्त्र किस ढंग से पहने गए हैं। गर्मियों में भी यदि चटक रंग कायदे के साथ और समय को ध्यान में रख कर पहने जाएं तो वे हल्के रंगों से भी ज्यादा प्रभावित करते हैं। अतः गर्मी के मौसम में आप सफेद और हल्के रंगों की धोतियां पहने, निःसन्देह वायल रंग-बिरंगी कढ़ी और पेन्ट की हुई साडियां मक्खन-जैसी मुलायम और परियों के पंख-जैसी हल्की लगती हैं। हल्की छपाई वाली साडियों की कोमलता एक खास ढंग से उभर कर आती है।

रंगों का समयानुकल परिवर्तन ही बहत कुछ जादू कर सकता है। आप एक ही रंग के विभिन्न सेडो को कई तरह से अलग-अलग ऋतुओं में पहन सकती हैं। वैसे बसंत ऋतु में तो रंगों की बहार होती है और ऐसे मौसम में जिस रंग के कपड़े आपके मन को भाएं उस रंग के कपड़े आप पहन सकती हैं। आमतौर पर पॉपलीन और कैबिक के हल्के गहरे रंगों में वाइल्ड प्रिन्ट्स, चैक, धारीदार या सफेद गहरे रंगों के कपड़े पसन्द किए जाते हैं। लेकिन इन सबके बीच वर्षा ऋतु के लिए इन्द्रधनुषी रंगों की शीफौन ऑर नॉयलोन जार्जट की छपी साड़ियों का कलेक्शन रखना न भूलें। #

ट्राइब वॉइस

TARIFF CARD

ADVERTISING RATES STRUCTURE 2020

AD POSITIONS	RATES	< Mega > Discount 50%
1. Full Page Back Cover (Multi Colour)*	Rs. 50,000/-	Rs. 25,000/-
2. Full Page Front Inside Cover (Multi Colour)*	Rs. 40,000/-	Rs. 20,000/-
3. Full Page Back Inside Cover (Multi Colour)*	Rs. 30,000/-	Rs. 15,000/-
4. Full Page (Black and White)	Rs. 20,000/-	Rs. 10,000/-
5. Half Page (Black and White)	Rs. 15,000/	Rs. 7,500/
6. Quarter Page (Black and White)	Rs. 10,000/-	Rs. 5,000/-

Hurry Up

Note: *Only Full Page and Colour
this offer till valid for December 2020

MECHANICAL DATA

Full Page: 26cm x 19cm
Half Page: 13cm x 19cm
Quarter Page: 9cm x 13cm

AD MATTER

Advertisement Designs in Photoshop, Corel draw and Images with matter.

Editorial Office

Address: 102, CG Heights, Prem Kunj, Civil Line, Raipur, Chattishgarh -492001
India

FOR SPACE BOOKING CONTACT:
TRIBE VOICE
E-mail: *manoj0000006@gmail.com*

ट्राइब वॉइस

SUBSCRIPTION FORM

Dear TRIBE VOICE ,

I / We would be interested in subscribing to "TRIBE VOICE" for year (s). I / We would be interested in availing myself / ourselves of the subscription offer in the Subscription Types. I / We am/are enclosing a Payment details Transaction No.____________________

dated____________________ Subscription Type____________________

NAME (M R. /MS. /M/S): ____________________

PROFESSION ____________________

ADDRESS ____________________

TEL NO. ____________________ MOBILE NO. ____________________

EMAIL ID____________________ WEBSITE ____________________

SUBSCRIPTION FEES STRUCTURE 2020

< Mega > Discount 50%

SUBSCRIPTION TYPES	FEES	Mega Discount 50%
1. Institutions (One Year)*	Rs. 600/-	Rs. 300/-
2. College / Universities (One Year)*	Rs. 350/-	Rs. 175/-
3. Students / Scholars (One Year)*	Rs. 300/-	Rs. 150/-
4. Individuals (One Year)*	Rs. 500/-	Rs. 250/-
5. Institutions (Five Year)*	Rs. 2500/-	Rs. 1250/
6. College / Universities (Five Year)*	Rs. 1300/-	Rs. 650/-
7. Students / Scholars (Five Year)*	Rs. 1100/-	Rs. 550/-
8. Individuals (Five Year)*	Rs. 2100/-	Rs. 1050/-

Note: *Single Copy Per Month

Hurry Up

TERMS & CONDITIONS

*>> Print*Subscription includes online access (Like PDF or E-Book).*

>> Students "should send a photocopy of their identity cards.

>> Print Subscription is Volume Based, whereas Online Subscription is Calendar Year Based and is subject to renewal.

>> Online Subscription (Like PDF or E-Book) includes current subscriptions and back files (for last 5 yrs, if available)

>> Delivery charges includes with subscription fees (notify if changes fees structure and other things). No needed addition fees.

>> If any changes required "TRIBE VOICE" magazine reserved all rights

ORDERING INFORMATION

FOR IMMEDIATE ATTENTION PLEASE CONTACT

TRIBE VOICE Office

Address: 102, CG Heights, Prem kKunj, Civil Line, Raipur, Chattishgarh -492001 India

E-mail: *manoj0000006@gmail.com*

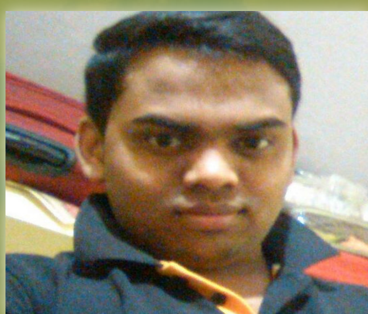

प्रदीप कुमार

"इस औद्योगिक युग ने पेड़-पौधों की कटाई की रफ्तार को आवश्यकता से अधिक बढ़ा दिया है। जिसके कारण वायुमंडल में कार्बन डाई आक्साइड की मात्रा में निरंतर इजाफा हो रहा है और ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। यदि एक समय बाद वायु प्रदूषण दर एक निश्चित बिन्दु तक पहुँच गया, तब ऐसी स्थिति में ताप संतुलन बिगड़ जायेगा।"

क्लाइमेट चेंज व ग्लोबल वार्मिंग

ठोस कदम उठाने की है जरूरत

"ईंधन के रुप में परम्परागत संसाधन जैसे कोयला, तेल तथा लकड़ियों का इस्तेमाल पर रोक लगना चाहिए, इसकी जगह नवीन तकनीकी व प्राकतिक गैसों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलना चाहिए। बिजली उत्पादन के लिए सौर उर्जा, पवन उर्जा, जल उर्जा के अलावा परमाणु शक्ति जैसे गैर-परम्परागत विकल्पों पर भी विशेष जोर दिया जाना चाहिए।"

इस आधुनिक औद्योगिक युग में अनगिनत कल-कारखानों और पेट्रोल व डीजल इंजनों से उत्सर्जित हानिकारक गैसों की वजह से वातावरण की स्वच्छ हवा निरंतर दूषित होती जा रही है। इसके अलावा ऊँची-ऊँची चिमनियों द्वारा भारी मात्रा में उत्सर्जित धुएं से भी हमारा वायुमंडल दिनोंदिन विषैला होता जा रहा है। इसतरह से वायुमंडल में लगातार विषैले गैसों की बढ़ती अधिकता के कारण जीव जगत को सांस की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जो कि धीरे-धीरे एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। जिस पर मानव समाज को विचार-विमर्श करना चाहिए।

वैसे तो हमारे वायुमंडल में जीव जगत के जीवन हेतु पर्याप्त मात्रा में जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस मौजूद है। लेकिन यदि वायु प्रदूषण की रफ्तार इसीतरह बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं, जब सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। यदि समय रहते वायु प्रदूषण पर काबू नहीं पाया गया तो धीरे-धीरे यह समस्या गंभीर व विकराल रुप लेती चली जाएगी, जिससे निपटने के लिए भविष्य में शायद ही कोई और विकल्प मौजूद होगा। हांलाकि, सूर्य के प्रकाश किरणों, हरे-भरे पेड़-पौधों तथा अन्य प्राकृतिक तत्वों के माध्यम से वातावरण अपना संतुलन स्वयं बनाए रखने को प्रयासरत रहता है। लेकिन उसकी भी एक सीमा है, यदि दूषित वायु की मात्रा एक निश्चित सीमा से अधिक हो गई तो फिर वातावरण स्वयं अपना संतुलन बनाए रखने में असक्षम हो जाएगा।

पर्यावरण में ऑक्सीजन का मुख्य स्त्रोत हरे-भरे पेड़-पौधें होते हैं। लेकिन इस औद्योगिक युग ने पेड़-पौधों की कटाई की रफ्तार को आवश्यकता से अधिक बढ़ा दिया है। जिसके कारण वायुमंडल में कार्बन डाई आक्साइड की मात्रा में निरंतर इजाफा हो रहा है और ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। यदि एक समय बाद वायु प्रदूषण दर एक निश्चित बिन्दु तक पहुँच गया, तब ऐसी स्थिति में ताप संतुलन बिगड़ जायेगा। इसके साथ-साथ भयंकर तूफान और मौसम में भारी बदलाव भी देखने को मिलेगें। जिसका सामना कर पाना मानव समाज के लिए लगभग अंसभव ही होगा।

आखिरकार वायु प्रदूषण पर काबू पाने का क्या तरीका हो सकता है। फिलहाल मनुष्य के पास जो भी तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ईंधन के रुप में परम्परागत संसाधन जैसे कोयला, तेल तथा लकड़ियों का इस्तेमाल पर रोक लगना चाहिए, इसकी जगह नवीन तकनीकी व प्राकतिक गैसों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलना चाहिए। बिजली उत्पादन के लिए सौर उर्जा, पवन उर्जा, जल उर्जा के अलावा परमाणु शक्ति जैसे गैर-परम्परागत विकल्पों पर भी विशेष जोर दिया जाना चाहिए। कल-कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का रिसाइकिल किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ वहां पर उपयोग में लाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए जीव वैज्ञानिक उपायों को अपनाया जाना चाहिए। तब जाकर कहीं हम अपने वातावरण की हवा को स्वच्छ व शुद्ध बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़ पायेंगे। #

क्या खूब जिया है जी भर...!

अच्छे लाल

ममता की छाँव तले,
शुकून से तूने तो जिया है खूब जी भर
हाँ एक आस रखी है किसी कोने में,
तू थिथोल तो जरा जी भर।
क्यों बिसरा दिए उस घरौंदे को,
जहाँ आराम मिला तुझे जी भर
दुनिया के हर रंग देखे हैं इस रहगुजर में,
हाँ तू देख तो जरा जी भर।।

किसी खूँटी में कोई बात टंगी है,
लेकिन तू ढूंढ़ तो जरा जी भर
हाँ अगर न ढूंढ़ सके तो,
अजमा अपनी परछाई को जरा जी भर।
कहीं मुकम्मल जहाँ न मिले तो न सही,
लेकिन बात तो रख जरा जी भर
सँवारने की हसरत है तुझे फिर से एक बार,
हाँ तू कदम तो बढ़ा जरा जी भर।।

वैसे तो क्या खूब मिला है तूझे तो, इस जमाने में
दर-बदर सा दिखता है, मुझे तू तो इस जमाने में।
यूँ ही जीते रहना भी क्या जीना है, इस जमाने में
पैदा हुए और चल दिए, बस क्या यही है फसाने में।।

तेरे गिर कर चलने से लेकर तेरे दौड़ने तक,
क्या खूब जिया है जी भर
तेरे सँवरने से लेकर तेरी उड़ान तक,
क्या खूब जिया है जी भर
वक्त करवटे लेता रहा पर किसने रोका,
क्या खूब जिया है जी भर
अभी तो कई बसंत बहार देखने है तुझे,
क्या खूब जिया है जी भर।।

तिनके-तिनके से तेरी आस में बनाया था घरौंदा,
क्या खूब जिया है जी भर
रात-दिन पाई-पाई जोड़कर दिलाई थी तुझे तालीम,
क्या खूब जिया है जी भर।
धूप-छाँव, भूख-प्यास की किसने की थी फिकर,
क्या खूब जिया है जी भर
क्या-क्या बताऊँ और क्या-क्या सुनाऊँ तूझे,
बस इतना है तुझसे कहना खूब जिया कर जी भर।।

RNI No. / Title Code: CHHHIN17199 | हिंदी मासिक पत्रिका | वर्ष: 01, अंक: 01, अगस्त -सितंबर | 2020 पेज-40

RNI No. / Title Code: CHHHIN17199 | हिंदी मासिक पत्रिका | वर्ष: 01, अंक: 01, अगस्त -सितंबर | 2020 पेज-40

जय जोहार, हरेली तिहार
के पावन दिवस से आरंभ

गोधन न्याय योजना

बढ़ेंगे रोजगार व आय के अवसर

- 2785 गौठानों से होगी गोधन न्याय योजना की शुरुआत
- 2 रु प्रति किलो की दर से होगी गोबर खरीदी
- 8 रु प्रति किलो में किसानों को मिलेगा वर्मी कम्पोस्ट
- गौपालन एवं गौ-सुरक्षा को प्रोत्साहन
- जैविक खेती को बढ़ावा
- खुली चराई पर रोक

पशुपालकों को लाभ पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य
छत्तीसगढ़

श्री भूपेश बघेल
मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

स्वच्छ छत्तीसगढ़ , स्वस्थ छत्तीसगढ़ , समृद्ध छत्तीसगढ़